



विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को संसद में रोका

विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, परिसीमन के मुद्दे पर विरोध किया

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक (131वां संविधान संशोधन विधेयक) और परिसीमन विधेयक सहित तीनों विधेयक दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण गिर गए।

इन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब मत विभाजन कराया तो कुल 528 वोट पड़े। इनमें समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।

परिणाम से स्पष्ट है कि महिला आरक्षण से कहीं अधिक परिसीमन को लेकर चिंता जता रहा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बावजूद अपने



विरोध से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। सरकार की ओर से यह समझाने की कोशिश हुई कि सीटें बढ़ेंगी तभी महिलाओं के लिए आरक्षण सही तरह से लागू हो सकेगा और सभी राज्यों में समान रूप से 50 प्रतिशत सीटें भी बढ़ेंगी।

शाह की ओर से शुक्रवार को यह तक कहा गया कि वह लिखित रूप में संशोधित विधेयक के अंदर भी इसे शामिल

करने को तैयार हैं। इस आश्वासन से दक्षिण के नेताओं में यह भरोसा जगता दिखा कि उनके राज्यों में सीटें बढ़ेंगी। लेकिन विपक्ष ने यह कहते हुए परिसीमन का विरोध किया कि इसकी आड़ में सीटों की संरचना में हेरफेर होगा।

विपक्ष की मंशा भांपकर प्रधानमंत्री ने पहले ही इस नैरेटिव की नींव रख दी थी कि विधेयक का विरोध करने वाले महिला

विरोधी होंगे और देश की नारी शक्ति उनकी नीयत देखेगी। शुक्रवार को पोस्ट कर उन्होंने सभी सदस्यों से स्वविवेक से वोट करने की अपली भी की थी। दो दिनों तक चली लंबी चर्चा के बाद मत विभाजन में मोदी सरकार की ओर से प्रस्तुत विधेयक दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। परिणाम घोषित होते ही विपक्षी खेमे ने मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की।

इसके साथ ही पूर्व में हुए प्रयासों की तरह महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की राह में राजनीतिक दलों के स्वार्थ और राजनीति फिर आड़े आ गई। जैसे ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा, वैसे ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष को

महिला विरोधी साबित करने की कोशिश की।

कांग्रेस के कारण महिलाओं को न्याय मिलने में देर होगी

सदन के बाहर भाजपा नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण महिलाओं को न्याय मिलने में देर होगी। सदन के बाहर राजग की महिला सांसदों ने काली तख्ती लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया।

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सदन में ही कह दिया कि हम सभी के पास महिलाओं को आरक्षण देने के ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने का अवसर था, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। माना जा रहा है कि यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा।

ये महिलाओं के हक के खिलाफ बड़ा खेल: अमित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शुक्रवार रात को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर मतदान के दौरान दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद एक संदेश में कहा उनका (कांग्रेस और सहयोगियों का) महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को अस्वीकार करना, उसका जश्न मनाना और जीत के नारे लगाना वास्तव में हिंदनीय और अकल्पनिक था। गृह मंत्री ने कहा आज लोकसभा में एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा गया, जब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उन्होंने आगे कहा अब देश की महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा, जो उनका अधिकार था। यह कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया है, पहली बार नहीं बल्कि बार-बार किया है। उनकी मानसिकता न तो महिलाओं के हित में है, न ही देश के। यह नारी शक्ति का अपमान है।

नया बिल महिलाओं और ओबीसी के खिलाफ है: राहुल

लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सदन में इस बिल की हार को विपक्ष की बड़ी सफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक सीधे तौर पर भारत के संविधान पर एक हमला था, जिसे हमने हरा दिया है। गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए साफ किया कि विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि यह महिलाओं का बिल नहीं है, बल्कि भारत की युगवी संरचना को बदलने का एक प्रयास है। लोकसभा में बिल गिरने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया। राहुल गांधी ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि महिलाएं हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं।

48 दिन बाद खुला होर्मुज, ट्रंप ने कहा- शुक्रिया

तेहरान। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और 48 दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद आखिरकार होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान ने घोषणा की है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से अब व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली रहेगी और उन्हें आने-जाने की पूर्ण छूट दी गई है। यह कदम लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद उठाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान में सीजफायर समझौते के अनुरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह खोल दिया गया है। विदेश मंत्री के अनुसार, यह निर्णय सीजफायर अवधि के शेष समय के लिए लागू रहेगा और पहले से घोषित समन्वित मार्ग के तहत सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा



निर्धारित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ईरान ने अभी घोषणा की है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग को खोलने का निर्णय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग के लिए राहत भरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम

क्षेत्रीय तनाव को कम करने और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है।

ईरान युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी संसद में खारिज

गौरतलब है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को सदन ने बृहस्पतिवार को एक वोट से खारिज कर दिया। प्रस्ताव के विरोध में 214 और समर्थन में 213 वोट पड़े।



रायपुर। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जशपुर जिले में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा का संचार किया है। रणजीता स्टेडियम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की विशेष मोबाइल प्रदर्शनी बस के आगमन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष गाड़ी का अवलोकन किया और प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह तथा विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के मॉडलों को देखा। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी वैज्ञानिक समझ और जिज्ञासा की सराहना की।

प्रमुख समाचार दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की मांग मंजूर नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हाजिर होकर अपने अतिरिक्त हलफनामा को रिकॉर्ड पर लेने की गुहार जस्टिस स्वर्ण कान्त शर्मा की अदालत के समक्ष लगाई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपर्ति जताते हुए कहा कि इसी तरह की मांग को पहले ही चीफ जस्टिस की बेंच खारिज कर चुकी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौजूदा कोर्ट इसे सुनना चाहे तो उन्हें कोई आपर्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। रजिस्ट्री भी इसे रिकॉर्ड पर ले कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वह इस हाई कॉपी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अपना हलफनामा दाखिल करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के इस अतिरिक्त हलफनामे पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात कोर्ट की यह टिप्पणी रही कि केस में पहले ही फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है।	मैं बंगाल की रक्षा के लिए लड़ूंगी : ममता कोलकाता। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कूच बिहार जिले की अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए सीएम ममता ने बंगाल की रक्षा करने, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इसकी धर्मनिरपेक्ष बनावट को बनाए रखने के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं खड़ी हूँ, मैं इन बांग्ला-विरोधी जमींदारों को इस धरती के लोगों पर कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं बंगाल की रक्षा के लिए लड़ूंगी, उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखूंगी जिनकी सेवा के लिए मैं चुनी गई हूँ, इस खूबसूरत राज्य के भविष्य को सुरक्षित करूंगी, और हमारी धर्मनिरपेक्ष बनावट और समावेशी भावना को हर उस ताकत से बचाऊंगी जो इसे तोड़ने की कोशिश करती रही है।मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पोस्ट में कहा कि मुझे आपकी जरूरत अपने पास है।	न्यायालय का काम समाज में विभाजन को रोकना है: राजीव धवन नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आस्था और परंपराएं न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। सबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जजों को किसी भी मामले पर फैसला सुनाते समय अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं को किनारे रखकर केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सांविधानिक ढांचे का पालन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान उन बुनियादी सवालों को कुरेदा, जो धर्म और संविधान के टकराव के बीच अक्सर खड़े होते हैं। वहीं, अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि यह लड़ाई सिर्फ एक मंदिर या एक समुदाय की नहीं है, बल्कि यह उन तमाम विश्वासों की है जो संविधानिक दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय का काम समाज में विभाजन को रोकना और सामंजस्य स्थापित करना है।	चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरु देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए ट्राईजेंट कैंप में तीर्थयात्रियों का पंजीकरण शुरु हो गया है। पंजीकरण काम का सुबह छह बजे से शुरु हुआ। जो शाम तक चला। वहीं चारधाम यात्रा प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से कल 18 अप्रैल शनिवार को सीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई।मुख्यमंत्री यात्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह छह बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरु कर दिया गया है। इसमें 24 काउंटर ट्राईजेंट कैंप में और छह काउंटर आईएसबीटी में खुले हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए तीस यात्रियों ने पंजीकरण कराया। वहीं यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी पीपी नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। वहीं एसडीएम ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने।	300 ग्राउंड कमांडरों के चेहरे खिले; पदोन्नति का वनवास खत्म नईदिल्ली। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में ग्राउंड कमांडर यानी सहायक कमांडेंट, जिन्हें 15वें साल में पहली पदोन्नति नहीं मिल सकी थी, अब उनके चेहरे खिल उठे हैं। सीआरपीएफ के लगभग 300 ग्राउंड कमांडरों का पदोन्नति का वनवास खत्म होने जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने विभागीय पदोन्नति कमेटी डीपीसी पर स्टे लगा रखा था। अब वह स्टे हट गया है। सीआरपीएफ मुख्यालय भी स्टे हटते ही तुरंत हरकत में आ गया। शुक्रवार को बल की सभी इकाइयों से कहा गया है कि उन सभी सहायक कमांडेंट की मेडिकल रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से मुख्यालय को प्रेषित की जाए, जिन्हें डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नति दी जानी है। बल मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि अगले सप्ताह पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सीआरपीएफ मुख्यालय ने 17 अप्रैल को सभी जोन, रफु सेंटर, यूनिटों एवं दूसरी इकाइयों को आदेश दिया है कि वे उन सहायक कमांडेंट (जीडी) की मेडिकल रिपोर्ट, अति आवश्यक आधार पर भेजें, जिन्हें डिप्टी कमांडेंट (जीडी) की पदोन्नति मिलने जा रही है। लंबे समय से यह केस सर्वोच्च अदालत में लंबित था।
---	---	--	--	--

विपक्षी एकजुटता के साथ सामाजिक न्याय का दांव चला

महिला बिल पर नया सियासी संदेश दे गया विपक्ष

हेमंत राजौरा

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को विपक्ष ने न सिर्फ संसद में पास होने से रोका बल्कि उसकी सियासी लड़ाई सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रही। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, बल्कि महिला आरक्षण बनाम परिसीमन, और ओबीसी प्रतिनिधित्व जैसे सवाल उठाकर एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में भी सफ़िय भूमिका निभाई। इस बहस ने आने वाले चुनावों के लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार कर दी है। दरअसल, इस विधेयक के खिलाफ विपक्ष के 230

सांसदों ने वोट दिया जबकि पक्ष में 298 वोट पड़े। विधेयक पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। आइए तीन प्वाइंट में समझें इससे विपक्ष को क्या हासिल हुआ...

एकजुटता का संदेश, इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा

महिला आरक्षण बिल के विरोध ने विपक्ष को एक मंच पर आने का मौका दिया। लंबे समय से इंडिया गठबंधन को बिखराव और आपसी मतभेदों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाकर विपक्ष ने एकजुटता का संकेत दिया।

कांग्रेस की पहल पर हुई बैठकों में



अलग-अलग दलों की भागीदारी ने यह दिखाया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बड़े मुद्दों पर साथ खड़े होने की इच्छा बनी हुई है।

पश्चिम बंगाल में तुणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्तों में तलखी, आम आदमी पार्टी का गठबंधन से अलग होना, और महाराष्ट्र में सहयोगी दलों की अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद, इस विरोध ने गठबंधन को नई ऊर्जा देने का काम किया।

महिला आरक्षण बनाम परिसीमन नैरेटिव की सीधी टक्कर

विपक्ष ने सरकार के महिला आरक्षण के नैरेटिव को सीधे चुनौती देते हुए इसे परिसीमन के मुद्दे से जोड़ दिया।

विपक्ष का तर्क रहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बजाय

परिसीमन के जरिए राजनीतिक संतुलन बदलना चाहती है।

इस नैरेटिव को दक्षिण भारत के कई नेताओं और मुख्यमंत्रियों का समर्थन मिला, जिन्होंने इसे संघीय ढांचे के लिए संभावित खतरा बताया।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाते हुए विरोध को तेज किया, जिससे यह बहस राष्ट्रीय स्तर से निकलकर राज्यों की राजनीति में भी गहराई तक पहुंच गई।

ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा केंद्र में

विपक्ष ने इस बहस को सिर्फ

महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे ओबीसी प्रतिनिधित्व और जातिगत जनगणना से जोड़कर व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया।

कई नेताओं ने सवाल उठाया कि बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान क्यों नहीं है।

साथ ही, सरकार पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश की।

यह रणनीति आने वाले समय में विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा बन सकती है।

बस्तर में भीषण गर्मी, सूख रही इंद्रावती नदी



जगदलपुर। बस्तर जिले में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। यहां का तापमान करीब 36 से 40 डिग्री के आसपास पहुंचने से इंद्रावती नदी समेत कई नदी-नालों का जलस्तर घट गया है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात में भी पानी की एक-दो धार बह रही है। इसका असर न केवल पर्यटन पर दिख रहा है, बल्कि पर्यावरण और जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। जहां आम दिनों में पर्यटकों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान से पहुंचे पर्यटक शिवम शर्मा ने बताया कि, वे चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन इस समय पतली धार ही नजर आ रही है। आली बार मानसून के बाद आना बेहतर रहेगा। वहीं बलौदाबाजार, बेमेररा और गरियाबंद से आए पर्यटकों ने भी पानी कम होने की बात कही, हालांकि उन्होंने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। गर्मी का असर केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव जल, जंगल और जीव-जंतुओं पर भी पड़ रहा है। नदी-नाले सूखने से पेड़-पौधों और वन्य जीवों के सामने जल संकट खड़ा हो रहा है। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी का भी जलस्त्रोत कम हो रहा है। इसी नदी पर चित्रकोट वाटरफॉल बना है। अभी अप्रैल का महीना भी खत्म नहीं हुआ और पारा चढ़ने लगा है। भीषण गर्मी को वजह से इंद्रावती नदी सूख रही है, जिससे एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट वाटरफॉल में भी एक पतली धार में पानी नीचे गिर रहा है। वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को अपनाएं, ताकि बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके। समय-समय पर जलक्रोतों की सफाई और गहरीकरण कर पानी को लंबे समय तक रोका जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और कटाई पर रोक लगाएं, जिससे भूजल स्तर बना रहे। अनावश्यक पानी की बर्बादी से बचें और दैनिक उपयोग में पानी का संतुलित इस्तेमाल करें। शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें। तरबूज, खीरा, नींबू पानी जैसे ठंडक देने वाले आहार लें। अधिक समय धूप में रहने से बचें और सिर को ढककर रहें।

वन विभाग की कार्रवाई पर ग्रामीण भड़के

■ घर का ताला तोड़कर लकड़ी जलत करने का आरोप, कोरबा में विरोध प्रदर्शन

कोरबा। कोरबा में वन विभाग की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। सतरंगा गांव के छह घरों से 359 नग चिरान जब्त करने के बाद ग्रामीणों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का



आरोप है कि वन विभाग ने पुराने लकड़ियों को जब्त किया है और कुछ घरों के ताले तोड़कर कार्रवाई की गई। यह मामला तब सामने आया जब डीएफओ प्रेमलता यादव को वन परिक्षेत्र बालको के सतरंगा

में अवैध वनोपज भंडारण की सूचना मिली। निर्देश पर वन विभाग की टीम गुरुवार सुबह सर्च वारंट के साथ गांव पहुंची। टीम ने सरकारी शिक्षक जगतराम निर्मलकर, महेत्तर सिंह, घांसी राम,

लच्छीराम और भगतराम के घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान साल, बीजा, हल्दू सहित अन्य प्रजाति के कुल 359 नग चिरान जब्त किए गए। वन विभाग ने इस मामले में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीण विशाल दास महंत ने बताया कि जब्त की गई लकड़ियों में पुरानी लकड़ियां भी शामिल हैं, जो उचित नहीं है। शिक्षक जगतराम निर्मलकर ने आरोप

लगाया कि उनके और उनके भाई के घर पर ताला लगा होने के बावजूद वन विभाग की टीम ने ताला तोड़कर लकड़ी बरामद की। उन्होंने बताया कि ये लकड़ियां पिताजी के खेत-खलिहान और जमीन अधिग्रहण में लगे पेड़ों को काटकर घर पर रखी गई थीं और काफी पुरानी थीं। ग्रामीणों ने डीएफओ को एक ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई की जांच करने और जब्त चिरान वापस करने की मांग की है।

सीएम देंगे 166 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

55 सड़कें और 12 बड़े पुलों का भूमिपूजन

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार को कबीरधाम जिले को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चौथा चरण) और पीएम जनमन योजना के तहत जिले में 166 करोड़ रुपए की लागत से 55 सड़कों और 12 वृहद पुलों का वरचुंअल भूमिपूजन किया जाएगा।

यह कार्यक्रम आज कवर्धा स्थित आचार्य पंथ श्री हकनाम साहेब बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित होगा, जहां से मुख्यमंत्री वरचुंअल माध्यम से जुड़कर निर्माण कार्यों की शुरुआत करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय कवर्धा विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे।

इन सड़कों और पुलों के निर्माण से जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद संतोष



पांडेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

रील बनाओ, इनाम पाओ, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

धमतरी। जिले की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरपूर वन क्षेत्र, शांत जलाशय और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने जिला प्रशासन की तरफ से आकर्षक रील एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। धमतरी जिले के पर्यटन क्षेत्र/स्थल विषय पर आधारित यह प्रतियोगिता 17 से 24 अप्रैल तक आयोजित हो रही है। इस पहल के माध्यम से प्रशासन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, बल्कि युवाओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सस्का मंच भी उपलब्ध कराना चाहता है। प्रतियोगिता में जिले के युवा, फोटोग्राफी प्रेमी, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और आम लोग भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को धमतरी जिले के प्रसिद्ध,



ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थलों जैसे गंगरेल बांध, रुद्री, सिहावा क्षेत्र के पर्वतीय दृश्य, घने जंगल, प्राकृतिक झरने, धार्मिक स्थल एवं ग्रामीण जीवन की झलक को अपनी रील या फोटोग्राफी के माध्यम से कैद कर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रतियोगिता के जरिए उन अनदेखे और कम चर्चित स्थानों को भी सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन मानचित्र में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। प्रतिभागियों को अपनी रील, फोटो और वीडियो व्हाट्सएप

नंबर +916268520889 पर निर्धारित अवधि के भीतर भेजनी होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रविष्टियां मौलिक होनी चाहिए और धमतरी जिले के किसी पर्यटन स्थल पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही, रील या फोटो की गुणवत्ता, प्रस्तुति और स्थान की विशेषता को भी महत्व दिया जाएगा। प्रतियोगिता की एक विशेष बात यह है कि इसमें विजेताओं का चयन पारंपरिक जजमेंट के बजाय सोशल मीडिया एंगेजमेंट के आधार पर किया जाएगा। जिस प्रतिभागी की फोटो या रील को सबसे ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट मिलेंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिससे युवाओं में उत्साह और रचनात्मकता को और बढ़ावा मिलेगा।

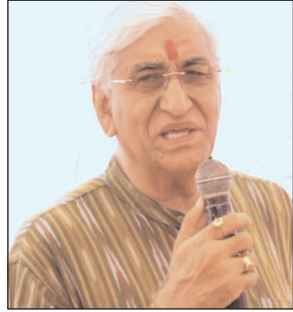
टिएस सिंहदेव ने कहा - मामला दुर्भाग्यपूर्ण

सरगुजिया भाषा बोलने पर बच्चे को नहीं मिला एडमिशन

■ पालकों ने निजी स्कूल पर लगाएं गंभीर आरोप

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरगुजिया भाषा बोलने के कारण एक 4 साल के बच्चे को निजी स्कूल में एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। मामला सौरंग किड्स एकेडमी का है।

अभिभावकों का आरोप है कि उनके बच्चे को स्कूल में एक सप्ताह तक डेमो क्लास में रखा गया, लेकिन बाद में यह कहकर एडमिशन देने से मना कर दिया गया कि बच्चा सरगुजिया भाषा



बोलता है, जिससे अन्य बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ गई है। लोग इसे क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं और दोषियों के

खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत बंसंत ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यदि सरगुजा में ही सरगुजिया भाषा बोलने पर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा विभाग से तत्काल जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे स्कूल को तत्काल बंद कर देना चाहिए।

सूरजपुर में शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी और मारपीट

सूरजपुर। भटगांव थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी और मारपीट की वारदात हुई है। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। चाकूबाजी की घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोंडी छिंदपारा गांव में गुरुवार को शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो युवकों का कुछ अन्य युवकों के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि 10 से ज्यादा युवकों ने एकजुट होकर दोनों युवकों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले लाठी-डंडों और मुकुओं से दोनों की जमकर पिटाई की, और उसके बाद चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर भटगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

बिलासपुर में गर्मी के चलते ट्रैफिक सिग्नल 4 घंटे बंद

बिलासपुर। बिलासपुर में भीषण गर्मी से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शहर के सभी 22 ट्रैफिक सिग्नल आज 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। यह व्यवस्था अस्थाई रूप से लागू की जाएगी। एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) रामगोपाल करियारे ने बताया कि, पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों और आम जनता को अत्यधिक गर्मी से राहत प्रदान करना है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि, सिग्नल बंद रहने के दौरान भी वे ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें। इससे शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा। यातायात पुलिस ने यह भी कहा है कि, गर्मी या लू के कारण किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की स्थिति में नागरिक यातायात अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे यात्रियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई।

1 लाख रुपये की रिश्तत लेते सरपंच को किया गिरफ्तार

महासमुंद। जिले मे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बेमचा सरपंच देवेंद्र चंद्राकर को 1 लाख रुपये रिश्तत लेते रगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच को पृष्ठताछ के लिए रायपुर लाया गया है। शहर से लगे ग्राम पंचायत बेमचा के खसरा नंबर 3110/3 के करीब 1 एकड़ 92 डिसमिल जमीन पर अजय कुर्ों नामक व्यक्ति का कब्जा था। इस जमीन को अजय कुर्े ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। इसमें से कुछ जमीन महासमुंद के महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत सूरज राम रात्रे को भी बेचा गया। जमीन के मामले में कुछ माह पूर्व जमीन कब्जाधारी अजय कुर्े का विवाद गांव के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ हुआ था। जिसके बाद मामला कोतवाली पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। बाद में बेमचा सरपंच देवेंद्र चंद्राकर ने जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने के एवज में 4 लाख रुपयों की मांग सूरज राम रात्रे से की। दोनों के बीच मामला भी सेट हो गया।

रायगढ़ में अपना ढाबा में 160 लीटर अवैध डीजल जलत

रायगढ़। जिला के ढाबा में अवैध रूप से डीजल की खरीदी-बिक्री की जा रही है। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपना ढाबा में दबिश दी और यहां प्लास्टिक जरकिन में भरे हुए 160 लीटर डीजल को जब्त किया है। पुलिस ने ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गारे में संचालित अपना ढाबा के संचालक द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डीजल को अवैध रूप से संग्रहित कर रखा गया है। जिससे किसी भी समय बड़ी घटना घटने की संभावना बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम ने तत्काल ढाबा पहुंची और मौके पर जांच की गई। ऐसे में यहां प्लास्टिक जरकिनों में 160 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। बरामद डीजल को 50-50 लीटर क्षमता वाली जरकिने में भर कर रखा गया था। ऐसे में जांच में यह पाया गया कि ढाबा संचालक के द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपाय के सार्वजनिक स्थल पर डीजल को अवैध रूप से बिक्री के लिए रखा गया था।

नशे-पेश के लिए बी-फार्मसी को छात्र बना चोर

कोरबा। कोरबा में अय्याशी-नशे की लत पूरी करने के लिए बी-फार्मसी छात्र ने अपने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उसने घर से सोने के जेवरात नेकेलेस, मंगलसूत्र, कान के झुमके और अंगूठी पार कर दिए। उसे बेचकर अपने शौक पूरे करने लगा। अब शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 60 हजार कैश और लगभग 8.2 ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र बरामद किया है। इस मामले में चोरी के जेवरत गलाकर बेचने वाले एक सुनार की तलाश की जा रही है। मामला सिविल लाइन रामपुर थाना इलाके का है। यह मामला 14 मार्च 2026 को सामने आया, जब एलआईजी-121 एमपी नगर कोरबा निवासी शिक्षिका सुनीता डोंगरे (पति वीरेंद्र कुमार डोंगरे) ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी अलमारी में रखे सोने के जेवरत 28 मार्च 2026 को गायब मिले। चोरी हुए सामान में नेकेलेस, मंगलसूत्र, कान के झुमके और अंगूठी शामिल थे, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपए थी।

बिलासपुर में दिन में अवैध उत्खनन, रात में परिवहन

■ सख्ती बरतने खनिज विभाग का ढाबा, 2 हाईवा और चैन माउंटेन समेत 6 वाहन जब्त

बिलासपुर। जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन थड़ुले से चल रहा है। शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में अवैध उत्खनन और परिवहन का वीडियो भी सामने आया है। दूसरी तरफ वीडियो वायरल होने के बाद खनिज विभाग ने दो हाईवा, एक चैन माउंटेन समेत 6 वाहन को जब्त किया है। ढाबा किया है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल, शहर से लगे सेंदरी, लाफंदी, कछार, बैमा, पेंडरवा, मोपका, कोनी, सरवन देवरी क्षेत्र सहित कई घाटों पर भारी मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए



नियमों को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। हालात यह हैं कि प्रतिस्पर्धा के चलते घाट पर ही ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो जाती है, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों को घेरने जैसी घटनाएं सामने आती हैं।

वहीं, तेज रफ्तार से दौड़ते खनन वाहनों के कारण ग्रामीण लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने खुलेआम अवैध उत्खनन और

परिवहन का वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अवैध उत्खन और परिवहन करते दिखाया गया है। साथ ही आरोप लगाया है कि खनिज माफियाओं ने मुरुम निकालने के लिए गांव में बड़े-बड़े गड्?दे खोद दिए हैं।

वहीं, नदी में जेसीबी, पोकलेन जैसी मशीन उतारकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आरोप है कि दिन में खनन और रात में परिवहन का खेल चल रहा है। लोगों का कहना है कि, अवैध खनन के चलते न केवल पर्यावरण और राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गांवों की सड़कों की हालत भी बदतर हो गई है। परिवहन में प्रतिस्पर्धा के चलते ट्रैक्टर और हाईवा गांव में तेज रफ्तार से चल रहा है, जिसके चलते सड़कों की हालत खराब हो रही है।

वहीं, खनिज विभाग के अफसरों का ढाबा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच राजस्व एवं खनिज विभाग ने संयुक्त रुप से टीम बनाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान तखतपुर, काठाकोनी, भरनी, चोरभट्टी, गनियारी, नेवरा, टांडा, अमने, मंगला और धुरिपारा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जिला खनिज अधिकारी केके गोलघाटे ने बताया कि, जांच के दौरान टीम जब ग्राम नेवरा पहुंची, तब पता चला कि यहां चैन माउंटेन लाइटकर मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस पर टीम ने चैन माउंटेन मशीन और 2 हाईवा समेत 6 गाड़ियों को जब्त किया गया है।

बिलासपुर में 12 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

बिलासपुर।

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले के 5 थाना इलाके से फरार 12 आरोपियों को पकड़वाने के लिए इनाम की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन फरार आरोपियों की सूचना देने वालों को पांच-पांच हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। फरार आरोपियों के संबंध में सूचना देने के लिए जिला पुलिस ने आला, अधिकारियों सहित संबंधित थाना प्रभारियों के नंबर जारी किए हैं। पुलिस ने कई गंभीर अपराधों में फरार इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है। इनमें थाना सकरी में दर्ज अपराध प्रकरण के आरोपी प्रशांत तिवारी (30) निवासी काठाकोनी और



रौनक धुर्वे (40) निवासी आसमा सिटी सकरी शामिल हैं। थाना तोरवा में दर्ज प्रकरण के आरोपी मोनिस हटकेश्वर, वासू हटकेश्वर, हनी हटकेश्वर (सभी निवासी बापूनगर) और पवन कुमार यादव (ग्राम डुङ्गा, थाना पामगढ़, जिला जांजीगर चांपा) और हिम बहादुर सोनार (निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल) भी इस सूची में हैं। इसी तरह थाना कोटा में दर्ज केस के आरोपी धार्मिक भाई सक्त्री (निवासी राधाकृष्णा अपार्टमेंट सीसीबी सूरत, जिला सूरत, गुजरात) और संतोष कुमार पोर्ते (निवासी जेमरा, थाना पाली, जिला कोरबा) पर भी इनाम

घोषित किया गया है। थाना तखतपुर में दर्ज केस के आरोपी परमेश्वर बैष्णव (निवासी जनकपुर रोड, थाना तखतपुर) और थाना बिल्हा में दर्ज अपराध प्रकरण के आरोपी गुरुजी उर्फ मेवालाल टंडन (55) निवासी बीरगंवा, थाना मुंगेली, जिला मुंगेली के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को भी पांच हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शहर बिलासपुर 9479193002; पुलिस नियंत्रण कक्ष, बिलासपुर 07758- 228504 और 9479193099। इसके अतिरिक्त, थाना प्रभारी सकरी 9479191721 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

एक ही परिस्तर में संचालित होंगे
अब राज्य के 7 विकित्ता परिषद



रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में पं. दी न द या 1 ल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई बैठक में राज्य की सभी चिकित्सा परिषदों (काउंसिल्स) को एक ही परिस्तर में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संस्थानों को कक्ष आवंटन आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था नवा रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के महर्षि संस्थान भवन में की गई है। आदेश में यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, आयुष काउंसिल, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, स्टेट फार्मसी काउंसिल, डेंटल काउंसिल और एलाइड हेल्थ काउंसिल को भूतल पर अलग-अलग कक्ष आवंटित किए गए हैं। सभी काउंसिल्स के रजिस्ट्रार और कार्यालय के लिए निर्धारित कक्ष और क्षेत्रफल तय कर दिए गए हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी परिषदें शीघ्र ही आवंटित कक्षों में स्थानांतरित होना सुनिश्चित करें। साथ ही, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल और पुस्तकालय का उपयोग सभी काउंसिल्स द्वारा साझा रूप से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण 4 मई से

रायपुर। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से 10 अप्रैल तक संचालित की गई थी जिसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 मई से 4 जून तक आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार विभाग के वेब पोर्टल ई-रोजगार.सीजी.जीओवी.इन अथवा मोबाइल पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला एवं विकासखंड स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आवेदक रोजगार कार्यालय रायपुर में संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, मुंबई से दबोचा गया खेमांनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय सट्टा गिराह के मुख्य आरोपी बानू खेमांनी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। उसे रायपुर लाया जा रहा है, जहां आगे की पुछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 20 सट्टोरियों को धर दबोचा था, जो अलग-अलग राज्यों से इस नेटवर्क से जुड़े थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह पूरा गिराह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था और करोड़ों रुपये का लेन-देन कर रहा था। मामले की शुरुआत तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक कार में बैठा व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से सट्टा चला रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक साथ कई राज्यों में छापेमारी की। मुंबई, ओडिशा और दुर्ग समेत कई जगहों से आरोपियों को पकड़ा गया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज और नकदी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है।

जसम छत्तीसगढ़ की पहली अध्यक्ष बनीं
रूपेंद्र तिवारी, सचिव बने राजकुमार सोनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जन संस्कृति मंच का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी हाल के दिनों में जसम का पहला राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का चयन भी किया गया। जसम छत्तीसगढ़ की पहली अध्यक्ष लेखिका रूपेंद्र तिवारी बनाई गई हैं, जबकि जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी प्रदेश जसम के भी सचिव बनाए गए हैं। लेखक और विचारक मुदित मिश्र बिलासपुर को उप सचिव नियुक्त किया गया है। सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक राजेश्वर सक्सेना, नंद कश्यप, आलोचक सियाराम शर्मा, जगदिव वासुकी प्रसाद उन्मत्, कथाकार कैलाश बनवासी और जितेंद्र गढ़वी को संरक्षक बनाया गया है। कवि हरगोविंद पुरी को मध्यप्रदेश जसम का समन्वयक और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जसम की रायपुर ईकाई से संबद्ध अजय शुक्ला, कवि घनश्याम त्रिपाठी भिलाई और निहाल सोनी बिलासपुर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। रायपुर जसम से संबद्ध सनियारा खान, भिलाई के साथी सुरेश वाहने और बिलासपुर जसम के योगेन्द्र साहू को सह-सचिव नियुक्त किया गया है। कोषाध्यक्ष पद को संभालने की जिम्मेदारी संस्कृतिकर्मी सुलेमान खान को सौंपी गई है। जसम की सांस्कृतिक टीम में रायपुर से वर्षा बोमपचे, सुनीता शुक्ला और समीक्षा नायर को शामिल किया गया है।

धर्मांतरण कानून पर बढ़ा विवाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

■ मंत्री बोले- गलत काम करने वालों की घबरहाट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लागू हुए धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 को लेकर सियासत और कानूनी बहस तेज हो गई है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसके प्रावधानों को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि कानून के कुछ प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

वहीं, इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं या अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वे खुद अपने कृत्यों पर संदेह जता रहे हैं। उनके मुताबिक, अगर सब कुछ सही होता तो इस तरह की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती।

सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन,



रखा गया है। दूसरी ओर, ईसाई समुदाय के लोगों का तर्क है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और निजी अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। उनका मानना ​​है कि संविधान के तहत हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता है, जिसे इस कानून के जरिए सीमित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो चुका है और इसके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद ही साफ हो जाएगा।

वेदांता हदसे पर भूपेश के बयान पर डिटी सीएम का पलटवार

■ कहा- ऑनलाइन होती है एफआईआर

रायपुर। वेदांता पावर प्लांट हदसे में चेयरमैन चैयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामला दर्ज हो चुका है। दुर्घटना बहुत बड़ी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि एफआईआर ऑनलाइन होती है, उन्हें लिंक बता दीजिए, तो वो देख लें।

बता दें कि वेदांता पावर प्लांट हदसे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्टर में सरकार पर एफआईआर को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वेदांता कंपनी के पूर्व हदसों का जिक्र करते हुए तत्कालीन भाजपा सरकार के



लीपा-पोती करते हुए कंपनी के मालिकों और ठेकेदार को बचाने का आरोप लगाया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। जो इसके विपक्ष में हैं वह भारत की मातृशक्ति को जवाब दें। महिलाएं जब साथ चलेंगी, तब भारत आगे बढ़ेगा।

सीबीएसई 10वीं परीक्षा का परिणाम होली क्रॉस स्कूल के विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर बढ़ाया गौरव

रायपुर। होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा सत्र 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि ने रायपुर सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

इस वर्ष अक्षरा पटेल ने 98.00 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। सार्थक केशरवानी ने 96.00 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय एवं ऋभभ मिश्रा ने 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में यश जैन (94.40 प्रतिशत), नमन खंडेलवाल (94.00 प्रतिशत), चाहत भट्टा (93.80 प्रतिशत), आदित्य पाधी (93.60 प्रतिशत), आयश कुमार



(93.20 प्रतिशत), अर्जु मेहता (92.60 प्रतिशत) और प्रयाग दास (92.60 प्रतिशत) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके अलावा यथार्थ पांडेय (91.40 प्रतिशत), शिवाक्षी नायक (90.80 प्रतिशत), जाह्नवी अग्रवाल (90.60 प्रतिशत), जाविन राठौड़ (90.40 प्रतिशत), शांभवी सिंह (90.40 प्रतिशत), प्रिशा वाधेरे (90.40 प्रतिशत), अम्रीतेश नंदे (90.40 प्रतिशत), रयान शर्मा (90.20 प्रतिशत), धार्या शर्मा (90.20 प्रतिशत), लक्ष्य अजय कवाडे (90.20 प्रतिशत), अनन्या जांधेल (90.00 प्रतिशत), ग्रेसी छाबलानी (90.00 प्रतिशत) एवं श्रेयश कुमार वर्मा (90.00 प्रतिशत) ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। इस वर्ष कुल 23 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण एवं शिक्षकों के समर्पण को दर्शाता है।

कांग्रेस ने वेदांता पावर प्लांट हदसे को बताया घोर लापरवाही का नतीजा

पीसीसी चीफ बैज ने कहा- हम नहीं जाते तो हो जाती लीपापोती, सरकार को कटनी चाहिए निष्पक्ष कार्रवाई

रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वेदांता पावर प्लांट में 3 दिन पहले हुए हदसे को घोर लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस का जांच दल वहां नहीं जाता तो मामले में लीपापोती हो जाती। हदसे पर सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व मंत्री सत्य नारायण शर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ वेदांता पावर प्लांट के मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद हर 3 महीने में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो रहा है। द्वाई साल में 300 से ज्यादा लोगों की औद्योगिक दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है।

हादसे के बाद वेदांता पावर प्लांट के निरीक्षण का जिक्र करते हुए बैज ने कहा कि कांग्रेस जांच दल ने अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की। मौके पर

भयावह स्थिति नजर आई। लोगों में दहशत का माहौल है। बंद पड़े एथेनॉल प्लांट को वेदांता ने खरीदा, साल भर पहले शुरू किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद प्लांट को चालू करने से पहले जरूरी है कमीशनिंग, लेकिन मौके पर जंग लगी मशीनों के साथ खराब पार्ट्स ही नजर आए, नए पार्ट्स नजर नहीं आए। बॉयलर ब्लास्ट से हुई मौतें सवाल उठता है कि क्या प्रेशर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था? वाटर लेवल इंडिकेटर की स्थिति भी संदिग्ध थी।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने पावर प्लांट हादसे को लेकर कहा कि 20 लोगों की मौत हुई हैं लेकिन बहुत ही सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज है। पर बैठे ही उनकी जमानत हो जाएगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गैर जमानती धाराएं नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने दोषियों पर बीएनएस की धारा 105 के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह बड़े उद्योगपतियों के समक्ष सरकार का संरंडर है।



नेता प्रतिपक्ष ने घटना की जांच सीनियर आईएएस के माध्यम से कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि एफआईआर में जांच के साथ ही पूरा संदर्भ होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने न्यायिक जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए न्यायिक जांच पूरी करा ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा बर्न यूनिट का निर्माण कराया जाए।

■ बारिश में किसी भी वार्ड में ना हो जल भराव की समस्या

रायपुर। नगर निगम जोन 1 कार्यालय पहुंचकर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर ने जोन अध्यक्ष गज्जू साहू एवं एमआईसी सदस्य नंदकिशोर साहू की उपस्थिति में जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल देवांगन सहित जोन 1 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ साहू को केदार कश्यप के बनाए गए ओएसडी

रायपुर। राज्य सरकार ने शैलाभ साहू को परिवहन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया है। यह प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शैलाभ कुमार साहू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति के साथ ही उप सचिव पुलक भट्टाचार्य को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ ई-ऑफिस, SPARROW, ई-एचआरएमएस तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्ष 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलाभ साहू ने बलौदाबाजार, गरियाबंद और सारंगढ़ जैसे जिलों में कार्य करते हुए प्रशासनिक दक्षता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने संसदीय चुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन कार्यालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। इसके अलावा उन्होंने परिवहन विभाग में लंबे समय तक आईटी का कार्य संभाला है।

भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप, मध्य छत्तीसगढ़ में पारा पहुंचा 44 डिग्री के करीब

■ 19 अप्रैल तक हीटवेव चलने की संभावना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तपती चुभती गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा।

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर हीट वेव



चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह स्थिति 19 अप्रैल तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि हीट वेव मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर चल सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में

अधिकतम तापमान 39 डिग्री से लेकर 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

मौसम विभाग के मुताबिक तीन दिन के बाद 1 से 2 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में

नमी की वजह से बादल छाए रहने के साथ ही एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है।

जिस तेजी से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना काम के घर से बाहर न निकलें। अगर जरूरी होता है तो इस दौरान अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने के साथ ही शरीर को पूरी तरह से ढंक कर ही बाहर निकलें।

चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति



संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा।

योजना के अंतर्गत चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही मेलों, उत्सवों और शासकीय कार्यक्रमों में इन कलाकारों को भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिल रही है।

चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृतिनई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देते हुए अनुभवी कलाकारों के मार्गदर्शन में युवाओं को पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चिन्हारी योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विलुप्त होती लोक परंपराओं का संरक्षण और पुनर्जीवन है। इसके तहत लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों के जरिए इन कलाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

गायत्री ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक

■ बारिश में किसी भी वार्ड में ना हो जल भराव की समस्या

रायपुर। नगर निगम जोन 1 कार्यालय पहुंचकर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर ने जोन अध्यक्ष गज्जू साहू एवं एमआईसी सदस्य नंदकिशोर साहू की उपस्थिति में जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल देवांगन सहित जोन 1 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते



हुए आवश्यक निर्देश दिये।

गायत्री सुनील चंद्राकर ने कर्मचारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की पुछता तैयारियां प्रशासनिक तौर पर जोन 1 के सभी 7 वार्डों में सिटी प्रोफाईल अनुसार अच्छी सफाई

करवाकर पाषांदो से समन्वय रखकर करने के निर्देश दिये हैं। स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष ने गंदे पानी का सुगम निकास का प्रबंध कायम करने बारिश पूर्व सभी नालों की अभियान पूर्वक तले तक पूर्ण सघन सफाई करवाना सुनिश्चित करने के

निर्देश जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी को दिये हैं ताकि जोन 1 क्षेत्र में बारिश में किसी भी वार्ड के किसी भी क्षेत्र मोहल्ले में जल के भराव की समस्या का सामना नागरिको को ना करना पड़े।

जनगणना प्रभारी ने मोहबाबाजार स्कूल प्रशिक्षण केन्द्र का किया औचक निरीक्षण



रायपुर। नगर निगम मुख्यालय जनगणना शाखा प्रभारी अधिकारी एवं निगम उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा ने जोन 8 जोन कमिश्नर एवं जोन 8 जनगणना चार्ज अधिकारी श्रीमती राजेश्वरी पटेल के साथ मोहबाबाजार स्कूल जनगणना प्रशिक्षण केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनगणना प्रशिक्षण ले रहे प्रमाणको एवं पर्यवेक्षको को दिये गये निर्देशानुसार समय सीमा के भीतर जनगणना कार्य त्रुटि रहित तरीके से पूर्ण करना प्राथमिकता बनाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

तो कहीं यूसीसी लागू नहीं किया जा रहा है। बैज ने कहा कि आदिवासियों की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है। सरकार आदिवासियों के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। सरकार कभी आदिवासी की चिंता नहीं करता। प्रदेश के चारों तरफ हाहाकार मचा है। सरकार छत्तीसगढ़ को उजड़ना चाहती है, ऐसा कांग्रेस होने नहीं देगी। संविधान कानून में सबको अपना अधिकार है। किसी के अधिकार को छिनने का हक, किसी दूसरे को नहीं है।

वहीं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस हमेशा से इसकी समर्थक रही है। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। कांग्रेस की सरकार ही इस बिल को लाई थी। जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन भी होना है। सरकार किस आधार पर परिसीमन करें, ये स्पष्ट करें फिर महिला आरक्षण लागू करें।

सम्राट को सुशासन का हस्तांतरण

मृत्युंजय दीक्षित

लम्बे संघर्ष और राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिल गया है। यह अवसर राजग गठबंधन के माध्यम से आया है। अभी तक बिहार में भाजपा जद (यू) के साथ छोटे भाई की भूमिका मे थी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जब बिहार से विधायक नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तभी से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति पर काम चल रहा था। बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मन बनाया और राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से लेकर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण तक सारी प्रक्रिया बहुत ही सधी हुई रही जिससे न तो विरोधी दलों को कोई अवसर मिला और न ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक नाराज होकर कोई गठबंधन विरोधी कार्य कर सके। बिहार में नीतीश कुमार के युग का नयी पीढ़ी के सम्राट को हस्तांतरण हो गया है। यह निश्चित है कि बिहार में केवल मुख्यमंत्री का केवल चेहरा बदला है सरकार नीतीश कुमार जी के निर्देशन व उनके किए गए कार्यों के आधार पर ही चलने वाली है। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के दो नेताओं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। अभी तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में गठबंधन की राजनीति में ऐसा सत्ता परिवर्तन किसी भी राज्य में कहीं भी नहीं देखा गया है। यह नेतृत्व परिवर्तन भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास लिख रहा है। मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता की 18 वर्षों से भी अधिक समय तक सेवा की वैसे ही अब सम्राट चौधरी भी 20 वर्षों तक बिहार की सेवा करने वाले हैं। कौन हैं सम्राट चौधरी- सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से युवा हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी के कोइरी समुदाय से आते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार के सर्वान्न समाज मे भी पसंद किया जाता है। सर्वणों के मुद्दों पर भी वह मुखर रहे हैं। सम्राट की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1990 में हुई और वे लालू यादव की राजद से वर्ष 2000 में परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक और लालू यादव की सरकार में मंत्री बने। 2014 में वो नीतीश कुमार जी के साथ आ गए किन्तु जदयू के साथ उनकी मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चली और वह 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। वर्ष 2023 में बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए गये। जनवरी 2024 में वह नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री बने और कई महत्वपूर्ण विभागों वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पंचायती राज को संभाला। मात्र आठ से नौ वर्षों मे ही उनकी भाजपा मे तेज तरक्की पार्टी की ओबीसी राजनीति और रणनीति का अहम हिस्सा है। भाजपा ने सम्राट चौधरी का चयन काफी सोच समझ कर किया है ताकि पिछड़ों–दलितों–महादलितों की सियास्तत में कोई नया खालीपन न पैदा हो। सम्राट चौधरी को भले ही भाजपा में बाहर से आया नेता बताया जा रहा हो किंतु वह काफी दमदार हैं और उनकी शैली आक्रामक है। वह लालू यादव के समीकरण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनकी राजनीति का सफर लालू यादव की राजद से ही प्रारंभ हुआ था और फिर वह नीतीश की पार्टी में भी गए और उसके बाद जीतराम मांझी के साथ रहे। सम्राट के माध्यम से भाजपा ने पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज को एक बहुत बड़ा राजनैतिक संदेश भेजा है। बंगाल में ओबीसी समाज का मतदता बड़ी संख्या में है। वर्ष 2027 की शुरुआत मे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हांगे उसको भी ध्यान में रखा गया है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

तब उसने नीचे के जबड़े को भूमि पर रखकर ऊपर के जबड़े को आकाश तक फैला लिया, और अपनी भीषण जीभके साथ आकाश के समान गहरे मुख में सब कुछ निगलने लगा॥ 27॥ इन्द्र वज्र के साथ उसकी कोख फाड़ कर बाहिर निकल आया, तथा बलपूर्वक शत्रु के मस्तक को काट कर पर्वत के शिखर की तरह भूमि पर गिरा दिया ।।32॥ (१) वृत्र के मरने पर ब्रह्महत्या इन्द्र के निकट पहुँची ।।10॥ इन्द्र ने देखा कि वह राजजीर्ण कलेवर वाली, तपेदिक के मरीज की तरह अस्थिपञ्जरावशिष्ट एवं रुधिर भरे वस्त्र ओढ़े चाण्डाली की भांति पीछे पीछे दौड़ती आ रही है॥12॥ अनन्तर ब्रह्मसावित्री द्वारा इन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया ॥16॥

जिसके पुण्य से त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर के वध का भहानू पाप विलट हो गया जैसा कि सूर्य से धुन्ध के बादल छाई माई हो जाया करते हैं। 20॥



वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विवेचन

ऊपर इन्द्र वृत्रासुर आख्यायिका के वैदिक और पौराणिक दोनों स्वरूप प्रकट कर दिये गये हैं। साक्षरवर्ग सहज में ही उक्त दोनों स्वरूपों की तुलना करने पर अनुमान कर सकेगा कि श्री वेदव्यास जी ने कितनी उत्तमता के साथ वेल्मन्त्रों का लौकिक अनुवाद करके वैदिक ज्ञान के भण्डार को सर्वसाधारणोपयोगी बना डाला है।

उक्त कथा के वैदिक स्वरूप में वृत्रासुर का विस्तृत शरीर, इन्द्र के साथ लोमहर्षकयुद्ध, त्वष्टा का शत्रुञ्जय यज्ञ करना, दधीचि की अस्थि से निर्माण किये वज्र द्वारा वृत्र का मरना, मृतमती ब्रह्महत्या का इन्द्र को आ घेरना एवं अन्त में अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से विशुद्ध होना आदि समस्त भाव किस खूबी के साथ अङ्कित किये गये हैं कि वे देखते ही बनते हैं।

क्रमशः ...

महावीर सिंघल

भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख रहे तात्या टोपे का 18 अप्रैल को यानी आज बलिदान दिवस है। तात्या टोपे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक गिने जाते हैं। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है।

छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवाओं ने उनकी विरासत को बड़ी सावधानी से सँभाला, अंग्रेजों ने उनका प्रभुत्व समाप्त कर पेशवा बाजीराव द्वितीय को आठ लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिदूर में नजरबन्द कर दिया, इनके दरबारी धर्माध्यक्ष रघुनाथ पाण्डुरंग भी इनके साथ बिदूर आ गये, इन्हीं रघुनाथ जी के आठ पुत्रों में से एक का नाम तात्या टोपे था।

1857 में जब स्वाधीनता की ज्वाला

तात्या टोपे



रही, इस युद्ध में तात्या के विश्वस्त साथी एक-एक कर बलिदान होते गये।

अकेले होने के बाद भी वीर तात्या टोपे ने धैर्य और साहस नहीं खोया। तात्या टोपे केवल सैनिक ही नहीं, एक कुशल योजनाकार भी थे उन्होंने झालरा पाटन की सारी सेना को कानपुर पर कब्जा कर लिया; यह देखकर अंग्रेजों ने नागपुर, महु तथा लखनऊ की छावनियों से सेना बुला ली अतः तात्या को कानपुर और कालपी से पीछे हटना पड़ा।

इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी में संघर्ष का बिगुल बजा दिया, तात्या ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, तात्या दो वर्ष तक सतत अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, चम्बल से नर्मदा के इस पार तक तथा अलवर से झालावाड़ तक तात्या की तलवार अंग्रेजों से लोहा लेती

(म.प्र.) के पास शिवपुरी के न्यायालय में एक नाटक रचा गया, जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित था।

सरकारी पक्ष ने जब उन्हें गद्दार कहा, तो तात्या टोपे ने उच्च स्वर में कहा- मैं कभी अंग्रेजों की प्रजा या नौकर नहीं रहा, तो मैं गद्दार कैसे हुआ ? मैं पेशवाओं का सेवक रहा हूँ जब उन्होंने युद्ध छोड़ा, तो मैंने एक पक्षे सेवक की तरह उनका साथ दिया, मुझे अंग्रेजों के न्याय में विश्वास नहीं है या तो मुझे छोड़ दें या फिर युद्ध बन्दी की तरह तोप से उड़ा दें। अन्ततः 18 अप्रैल 1859 को उन्हें एक पेड़ पर फाँसी दे दी गयी कई इतिहासकारों का मत है कि तात्या कभी पकड़े ही नहीं गये जिसे फाँसी दी गयी, वह नारायणराव भागवत थे, जो तात्या को बचाने हेतु स्वयं फांसी चढ़ गये, तात्या सन्यासी वेप में कई बार अपने पूर्वजों के स्थान येवला आये।

कतिलाल मांडेठ

लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश होने के साथ ही देश की राजनीति एक नए चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। इन विधेयकों पर चर्चा के लिए सदन में लंबा समय तय किया गया है और इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का बड़ा प्रश्न बन चुका है। चर्चा के लिए पहले मतदान हुआ जिसमें बहुमत ने इस विषय पर बहस को मंजूरी दी और अब सभी दल अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में हैं।

यह पूरा घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून को संसद से मंजूरी मिली थी। उस समय इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था लेकिन इसके लागू होने की समयसीमा जंगणना और परिसीमन से जुड़ी शर्तों के कारण आगे खिसकती नजर आ रही थी। अब सरकार ने संशोधन के जरिए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लागू करने की समयसीमा को आगे लाने की कोशिश की है ताकि वर्ष 2029 के आम चुनावों तक इसका प्रभाव दिखाई दे सके।

नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने की योजना है। वर्तमान में यह संख्या 543 है। इस विस्तार के साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के स्वरूप का भी संकेत देता है क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल आ सकता है।

सरकार का तर्क है कि यह संशोधन सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार ऐसे बदलाव जरूरी होते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार यह भी स्पष्ट कर रही है कि परिसीमन की प्रक्रिया को नई जंगणना के बजाय 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिससे देरी कम हो और कानून जल्दी लागू हो सके।



वहीं विपक्ष ने इस पूरे प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण का वे समर्थन करते हैं लेकिन परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए राज्यों के बीच संतुलन बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और यह संघीय ढांचे के लिए चुनौती बन सकता है। कुछ नेताओं ने इसे समाज को वर्गों में बांटने की साजिश भी बताया है।

राजनीतिक बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके जवाब में सरकार की ओर से यह कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और यह संभव नहीं है। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

इस पूरे विवाद में परिसीमन सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है। परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक सीटों का निर्धारण 1971 की जंगणना के आधार पर किया जा रहा था लेकिन अब इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के तहत संसद को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह तय करे कि किस जंगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए।

इस बदलाव का असर राज्यों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों को सीटों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सीटों का अनुपात घट सकता है। यही कारण है कि

तमिलनाडु और अन्य राज्यों के नेताओं ने इसका विरोध किया है और इसे क्षेत्रीय असंतुलन की ओर कदम बताया है।

महिला आरक्षण के प्रभाव को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और कुल सदस्यों का लगभग चौदह प्रतिशत ही महिलाएं हैं। राज्यसभा में भी यह प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है और कई छोटे देश भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आगे हैं। ऐसे में यह कानून भारत को इस दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखता है।

हालांकि इसके साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। आरक्षित सीटों का रोटेशन हर चुनाव में होगा जिससे नेताओं को अपने क्षेत्र बदलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और अधिक संख्या में महिला उम्मीदवारों को तैयार करना होगा। यह बदलाव केवल कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन से ही सफल हो सकता है।

संविधान संशोधन होने के कारण इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि केवल साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई समर्थन जरूरी होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास बहुमत है लेकिन दो तिहाई समर्थन के लिए उसे अन्य दलों से भी सहयोग लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि बैक चैनल बातचीत और राजनीतिक सहमति इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी।

महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है बल्कि यह पिछले तीन दशकों से चर्चा में रहा है। कई बार इसे संसद में पेश किया गया लेकिन विभिन्न कारणों से यह पारित नहीं हो सका। वर्ष 2010 में इसे राज्यसभा से मंजूरी मिली थी लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। अंततः वर्ष 2023 में इसे कानून का रूप मिला और अब संशोधन के जरिए इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि

ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग बढ़ाकर मोदी ने किया कमाल

नीरज कुमार दुवे

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। लगभग चार दशकों के बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का भारत आगमन न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती का संकेत है, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में बदलती प्राथमिकताओं के बीच नई साझेदारी के निर्माण का भी प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही असरचरन्ना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं, रोपवे, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल पंद्रह महत्वपूर्ण समझौते और पहलों सामने आईं, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति देने के लिए सैन्य मामलों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर सहमति बनी है। इसके तहत रक्षा उद्योग, नीति



संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी।

आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रेक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। इससे व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया गया है, जिससे दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत वैज्ञानिक सहयोग, मानकों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इससे कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षुता प्रणाली, ज्ञान साझा करने और योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संरचित संवाद शुरू करने और तकनीकी विशेषविद्यालयों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है।

इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा संवाद शुरू करने, अंतरिक्ष उद्योग में संयुक्त सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम को लागू करने जैसी घोषणाएं भी की गईं। उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्रांतिम तकनीक, मशीन लर्निंग, जल शोधन

और सामग्री विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान को साझेदारी का मुख्य आधार बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर सकती है। उन्होंने रक्षा, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और क्रांतिम क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में हुए प्रवासन और गतिशीलता समझौते के तहत अब नर्सिंग क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, दोनों देशों ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख द्वार है और हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत इंजीनियरिंग में इसकी विशेषज्ञता भारत के विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह लगभग तीन अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है।

देखा जाये तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रभाव वैश्विक भू-राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु का काम करता है, जिससे भारत को यूरोप के बाजारों, तकनीक और निवेश तक बेहतर पहुंच मिलती है। इस सहयोग से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और अधिक मजबूत होगी, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही, ऑस्ट्रिया का भारत के प्रति समर्थन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर। दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह साझेदारी भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्नत तकनीक, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय नेतृत्व को और प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकेगा। इससे न केवल भारत की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि वह क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलन बनाए रखने में भी अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेगा।

बहरहाल, ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के संबंध अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नवाचार केंद्रित और भविष्य उन्मुख साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे सहयोग मॉडल की नींव रखी है जो न केवल द्विपक्षीय हितों को साधेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और प्रगति में योगदान देगा।

आज का इतिहास

1906 एक बड़ा भूकंप और जिसके परिणामस्वरूप आग ने सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया (क्षति का चित्रण), कम से कम 3,000 लोगों की मौत और शहर की आबादी के बेघर होने की अधिक संभावना को छोड़कर।

1923 मेजर लीग बेसबॉल के न्यूयॉर्क यांक्रीज़ ने नवनिर्मित यांकी स्टेडियम में खेल खेलना शुरू किया।

1938 सुपरमैन, जेरी सिगएल और जो शस्टर द्वारा बनाई गई, एक्शन कॉमिक्स 1 में पहली सच्ची सुपरहीरो कॉमिक बुक में अपनी शुरुआत की।

1947 सबसे बड़े गैर-परमाणु एकल विस्फोटक डेटोनेशन इतिहास में, रॉयल नेवी ने हेलिगोलैंड, जर्मनी के द्वीप को नष्ट करने के असफल प्रयास के साथ 4,000 टन अधिशेष गोला बारूद स्थापित किया।

1949 आयरलैंड ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया और वे रिपब्लिक बन गए।

1952 पश्चिमी जर्मनी और जापान ने राजनयिक संबंध स्थापित किये। 1958 विवादास्पद अमेरिकी कवि एजरा पाउंड को वाशिंगटन डी.सी. के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल से रिहा कर दिया गया था, जहां उन्हें बारह साल तक कैद रखा गया था।

1971 वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में सुनील गावस्कर ने 220 रन बनाए। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए थे। 1983 1983 में बेरूत के संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास पर बमबारी से 63 लोग मारे गए।

1994 ब्यूटी एंड द बीस्ट को न्यूयॉर्क शहर के पैलेस थिएटर में रिलीज़ किया गया था।

1994 98 वाँ बोस्टन मैराथन केन्या के कोस्मस नडेती ने जीता था। उन्होंने सिर्फ़ 2 घंटे 7 मिनट 15 सेकंड में मैराथन पूरी की।

1994 ब्रायन लारा ने लिटल शटक बनाया। उन्होंने एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन बनाए। 1996 न्यूयॉर्क शहर के सेंट जेम्स थिएटर में मजेदार बात हुई जारी किया गया था। यह 715 दिनों तक हाउसफुल चला।

1999 ब्रिटेन की प्रमुख उपन्यासकार, जीवनीकार और सम्पादक मैरी बुलिंग्स का 90 वर्ष की आयु में निधन।

2010 देश संपीत पुरस्कार के 45 वें अकादमी कैरी अंडरवुड, ब्राड पैसले और मिरांडा लैम्बर्ट ने जीता।

2011 पूर्वी जावा में एक लैंड-स्लाइड हुआ। घटना में लगभग 100 लोग मारे गए थे।

2013 इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम धमाकों में 27 की मौत, 65 घायल।

बिहार में विकास संबंधी चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा नए सम्राट को!

कमलेश पांडे

बिहार के नए सम्राट को फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, या पूर्व मुख्यमंत्री दम्पति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कभी भी चैन पूर्वक राज नहीं कर सके। लिहाजा, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उन जातीय और साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझना होगा, जो बिहार के विकास में शुरू से ही बाधक समझी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को कांग्रेस से सहयोग से लंबे समय तक राज करते हुए जनसेवा का मौका मिला, वैसी ही मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा के सहयोग से जनसेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि पार्टी ने उन्हें पद नहीं, जनसेवा का अवसर दिया है, इसलिए विकास, सुशासन और समृद्धि उनके शासन का मूलमंत्र होगा।

बिहार के आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की, प्रगति नजर भी आई, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और हाल के वर्षों में उत्तरप्रदेश के विकास को देखा जाए तो अब भी बिहार के विकास में कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं,

जो आंकड़ों और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने पर साफ दिखती हैं। इसलिए भाजपा की सरकार के सुलझे हुए और समावेशी प्रवृति वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बिहार के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से जूझना होगा। लेकिन अपने मृदु स्वभाव से वे एक एक करके इनसे पार पा जाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

पहला, निर्धनता, रोज़गार और मानव पूंजी के नजरिए से विकास– आंकड़े बताते हैं कि बिहार, भारत के सबसे कम आय वाले राज्यों में शुमार है, जहां गरीबी दर अभी भी काफी ऊँची है और रोज़गार की गुणवत्ता कमजोर है। समझा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण यहां की मानव पूंजी कमजोर है– साक्षरता और स्किल लेवल अभी भी देश के स्तर से काफी नीचे हैं, जिससे युवाओं को अच्छे रोज़गार के अवसर मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे में यदि अपराध, जातीय सोच और सांप्रदायिक मिजाज को हेतोसाहित करके इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसके लिए अप्रवासी बिहारियों और बिहार मूल के एनआरआई को आकर्षित करने वाली योजनाओं को बनाना होगा और उनपर दृढ़तापूर्वक अमल करना होगा।

दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के



चलते उत्पादकता बढ़ाने पर देना होगा ध्यान– यद्यपि हार की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्पादकता और आय दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसा इसलिए कि उत्तर बिहार 4 महीना बाढ़ से आक्रांत रहता है और तभी दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा होता है। खेती और बागवानी यहां पर होती तो है, लेकिन भंडारण सुविधाएँ, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और बारहमासी सिंचाई की सीमित पहुँच जैसे कारकों के कारण कृषि अभी भी बहुत जोखिम भरी और कम लाभ वाली काम साबित होती है। लिहाजा किसानों और मजदूरों के बच्चे परदेश कमाने चले जाते हैं और अपनी उद्यमिता से सबको सुख पहुंचाते हैं।

तीसरा, औद्योगिक विकास और निवेश की दिक्कत सबसे बड़ी अड़चन– बिहार में 26 साल पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग–धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। ततपश्चात छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन और वित्तीय अभाव के कारण इनका समग्र विस्तार नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। इस कारण और निजी निवेश की दृष्टि से बिहार अभी भी निवेश अनुकूल राज्यों की पहली पंक्ति में नहीं है, बल्कि तेजी के साथ उद्योग बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को चाहिए कि वह महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर बिहार–उत्तरप्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में औद्योगिक रफ्तार तेज होने से लुक ईस्ट की विदेश नीति को मजबूत आधार मिलेगा।

चौथा, बुनियादी ढांचा और शहरीकरण में निवेश और विस्तार– बिहार में सड़क नेटवर्क, बिजली, जल सुविधा, नालियाँ, जनस्वास्थ्य

और शहरी बुनियादी ढांचा अभी भी प्रमुख रूप से कमजोर जगह बनी हुई हैं। चाहे स्थापित शहर हों या कस्बाई शहर, यहां शहरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिससे औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था को उतना बल नहीं मिल पा रहा जितना दूसरे विकसित राज्यों में मिला है। इसलिए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार के सृजन में इस क्षेत्र का बड़ा इगड्ड होता है।

पांचवां, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर करना– बिहार के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद कमजोर हैं– खासकर डॉक्टर आबादी अनुपात कम, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है और कुपोषण जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीरबनी हुई हैं। इसी तरह पीडीएस (ऋष्ट), राशन, योजनाओं के वितरण में धांधली, रिसाव और कार्यान्वयन की कमजोरी विकास के लाभों को गरीबों तक पहुँचने से रोकते हैं। इस स्थिति में अमूलचूल बदलाव लाना होगा, ताकि स्थिति बदले।

छठा, शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर कम ध्यान– बिहारी में जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें बंथती हैं, लेकिन बाद में सबकुछ पुराने ढ़र पर

चलने लगता है। अब इस स्थिति को बदलना होगा। क्योंकि कई रिपोर्टों में बिहार को भ्रष्टाचार, निष्पक्ष नियोजन और प्रशासनिक दक्षता की दिक्कत से जूझता हुआ देखा गया है, जिससे बजट का अच्छे तरीके से उपयोग होना मुश्किल होता है। वहीं, कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी निवेशक और नागरिक दोनों के लिए चिंता का मुद्दा है। इसलिए नए मुख्यमंत्री को इसे समझना होगा और विशेष टास्क फोर्स का गठन कर इस स्थिति को बदलना होगा। इसी में बिहार का हित निहित है।

सातवां, क्षेत्रीय असमानता और जाति धर्म की संवेदनशील राजनीति– अनुभव बताता है कि बिहार में अलग अलग जिलों के बीच विकास का अंतर बढ़ा है; कुछ शहर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र विकास समीक्षा चक्र से बाहर रह जाते हैं। साथ ही, जाति आधारित राजनीति और आरक्षण संबंधी विवाद नीतियों को लंबे समय तक टिकाने और निष्पक्ष ढंग से लागू करने में बाधा बनते हैं। इसलिए सुझबूझ पूर्वक इन चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। इससे सबका हित सधेगा और बिहार विकास के नए कीर्तिमान खड़े करेगा। इस यश नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिलेगा। भाजपा को मिलेगी।

अमरीका–ईरान के बीच युद्धविराम नहीं अल्पविराम

बलबीर पुंज

दुनिया कई बार ऐसे मोड़ों पर आ खड़ी होती है, जहां शांति का हर दावा खोखला और जीत का हर शोर अधूरा लगता है। ईरान और अमरीका–इसराइल टकराव का ताजा अध्याय भी कुछ ऐसा ही है–ऊपर से सन्नटा, भीतर से सुलगता हुआ संघर्ष। दोनों के बीच हुए 2 हफ्तों के युद्धविराम की... दुनिया कई बार ऐसे मोड़ों पर आ खड़ी होती है, जहां शांति का हर दावा खोखला और जीत का हर शोर अधूरा लगता है। ईरान और अमरीका–इसराइल टकराव का ताजा अध्याय भी कुछ ऐसा ही है–ऊपर से सन्नटा, भीतर से सुलगता हुआ संघर्ष। दोनों के बीच हुए 2 हफ्तों के युद्धविराम की घोषणा ने दुनिया को उस खाई के किनारे से खींच लिया, जहां हालात किसी महाविनाश की ओर बढ़ते दिख रहे थे। दोनों पक्ष खुद को विजेता बता रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि यहां किसी की साफ जीत नहीं हुई, यह दोनों के लिए नुकसान का सौदा अधिक है। नि:संदेह, इस संघर्ष में अमरीका और ट्रम्प की साख को जबरदस्त झटका लगा है। ट्रम्प प्रशासन इस युद्धविराम को अपनी रणनीतिक सफलता बताते हुए दावा करता है कि उसने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए मजबूर किया लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह समुद्री मार्ग तमाम बयानबाजी के बावजूद कभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, न फरवरी 2026 से पहले और न ही 2023 में इसराइल पर हमास के भीषण हमले या 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमरीका–इसराइल हमलों के बाद। ऐसे में जो समुद्री मार्ग इस युद्ध से पहले वर्षों से खुला हुआ था, उसे अमरीका द्वारा फिर से खुलवाना, वह भी मात्र 15 दिन के लिए और उसे अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करना, कुतर्क और हास्यास्पद है। उसका उद्देश्य कभी होर्मुज रहा ही नहीं था। दरअसल, ‘एपिक फ्यूरी’ (2026) और ‘मिंडनाइट हैमर’ (2025) जैसे अमरीकी सैन्य अभियानों के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और वहां सत्ता परिवर्तन लाना अमरीका का असली मकसद

था। लेकिन इतनी ताकत झोंकने के बावजूद ये लक्ष्य पूरे नहीं हुए। सैकड़ों भीषण मिसाइल–ड्रोन हमलों से ईरान का परमाणु ढांचा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सबसे अहम, ईरान में जिस आंतरिक विद्रोह या इस्लामी सत्ता के ढहाने का प्रयास अमरीका कर रहा था, वह पूरी तरह असफल हुआ। युद्धविराम से कुछ घंटे पहले ही ट्रम्प की चेतावनी, ‘आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी’ बताती है कि हालात कितने खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुके थे। सबसे बड़ी चूक शायद यही रही कि अमरीका ने वर्तमान ईरान की मानसिकता को समझने में रणनीतिक भूल कर दी। ट्रम्प की लेन–देन वाली और बदजबान कूटनीति ने ईरानी जिद और लड़ने की ताकत को कम आंका। लगभग 5 दशकों में अयातुल्ला के इस्लामी शासन ने ऐसे लाखों फिदायीनों को तैयार किया, जो मजहबी कारणों से मरना पसंद करते हैं। वे इस्लाम के लिए शहादत को एक उच्च आदर्श मानते हुए दूसरी दुनिया (जन्नत) में मिलने वाले पुरस्कारों की कामना करते हैं। यही विचारधारा ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। दूसरी ओर, ईरान ने तेजी से इस युद्धविराम को अपनी जीत के रूप में पेश किया। उसके आधिकारिक बयानों में इसे अमरीका की ‘करारी हार’ बताया गया और दावा किया गया कि अमरीका को उसकी कई शैंते माननी पड़ीं, जैसे प्रतिबंधों में ढील, परमाणु संवर्धन के अधिकार की मान्यता और होर्मुज जलडमरूमध्य में उसकी भूमिका को स्वीकार करना। लगातार हमलों के बावजूद टिके रहकर ईरान ने स्वयं को आंतरिक रूप से और क्षेत्रीय राजनीति में पहले से अधिक मजबूत किया है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि इस मध्यस्थता के लिए भारत की बजाय पाकिस्तान को क्यों तरजोह मिली? बल्कि असली सवाल यह है कि क्या भारत को भी वही करना चाहिए था, जो पाकिस्तान ने ट्रम्प को खुश करने के लिए किया? पाकिस्तान ने सुनिश्चित राजनीतिक और आर्थिक चालें चलीं। जून 2025 में पाकिस्तान ने ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया।

विकास मिश्रा

पिछले दशकों का यदि आप लेखा–जोखा लें तो अमेरिकी फौज कहीं न कहीं, कोई न कोई जंग लड़ती ही रही है। तो कारण क्या है? विश्व के सबसे ताकतवर और महारथी माने जाने वाले देश को इतनी जंगें क्यों लड़नी पड़ती हैं? क्या जंग उसकी निजी पसंद है या फिर जंग उसके सिर पर आ गिरती है? जंग से अमेरिका को क्या वाकई कोई नुकसान होता है या फिर उसका हथियार उद्योग जंग में मुनाफा कमाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में उठते रहते हैं। जवाब तलाशने की कोशिश करें तो दो नजरिया सामने आता है। एक नजरिया अमेरिका का है और दूसरा नजरिया उनका जो अमेरिकी जंग के शिकार होते हैं।

अमेरिका के ढाई सौ वर्षों के इतिहास पर यदि नजर डालें तो दो दशक भी मुश्किल से निकल कर आएंगे जब अमेरिका जंग से अछूता रहा है। यदि कभी जंग में सीधे शामिल नहीं रहा है तो किसी जंग में एक पक्ष के साथ न केवल हथियारों बल्कि वित्तीय मदद के साथ खड़ा रहा है। हाल के वर्षों में इसका उदाहरण रूस और यूक्रेन को जंग है जिसमें यूक्रेन की अमेरिका ने खूब मदद की है।

आधुनिक अमेरिकी वक्त में केवल जिमी कार्टर ऐसे राष्ट्रपति नजर आते हैं जिनके कार्यकाल 1976 से 1980 के बीच अमेरिका ने किसी भी देश के खिलाफ जंग नहीं लड़ी। जब वे राष्ट्रपति थे तब ईरानी क्रांति हुई और ईरानियों ने अमेरिकी दूतावास में सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। उन बंधकों को छुड़ाने के अभियान में आठ लोगों की मौत हुई थी।

उन मौतों को छोड़ दें तो किसी की भी मौत अमेरिकी युद्ध में नहीं हुई। कार्टर ने हर समस्या का कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश की। परमाणु हथियारों में कमी के लिए सोवियत संघ के साथ बातचीत की पहल उन्होंने ही की थी। यहां तक कि इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष को भी सुलझाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश को कई अमेरिकियों ने ही विफल किया।

जिमी कार्टर के उत्तराधिकारी रोनाल्ड रीगन ने भी हालांकि किसी देश पर सीधा हमला नहीं किया लेकिन लेबनान में उन्होंने हस्तक्षेप किया और वहां अमेरिका के दो



सौ से ज्यादा सैनिक मारे गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश (2001–2009) के हिस्से में अफगानिस्तान और इराक की जंग है। बराक ओबामा (2009–2017) के कार्यकाल में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा था। जो बाइडेन के दौर में भी अमेरिका जंग लड़ ही रहा था। ट्रम्प आए तो उन्होंने शांति का ऐसा राग अलापा कि पूरी दुनिया को लगा कि ये शाख्व अमेरिकी नीतियों को बदल देगा।

नोबल प्राइज की उनकी चाहत ने संदेश दिया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका अब शांति की राह पर है। मगर फिर सबकुछ उलट–पुलट हो गया। वे ईरानियों के खून के प्यासे हो गए। मगर ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया है उसने यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया का ये चौधरी जंग शुरू तो करता है लेकिन उसे समेट क्यों नहीं पाता? किसी लक्ष्य पर क्यों नहीं पहुँच पाता है?

अमेरिकी जंगों का इतिहास देखें तो दूसरे विश्व युद्ध और उससे पहले अमेरिका ने जितनी भी जंगों में भाग लिया, उन सब में अमेरिका की जीत हुई। मगर 1945 के बाद ज्यादातर जंगों में उसकी जीत स्पष्ट नहीं थी। अफगानिस्तान में तालिबान फिर राज कर रहे हैं। तमाम हमलों के बावजूद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है।

वियतनाम जंग के बारे में तो बात ही क्या करें, अमेरिका को बहुत बेआबरू होकर वहां से निकलना पड़ा था। ईरान में भी अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, यही स्पष्ट नहीं है। तो अमेरिका हमले क्यों करता है? सीधे

तौर पर अमेरिका का मानना है कि दुनिया में मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा करने का उसे नैसर्गिक अधिकार है।

कहीं भी लोकतंत्र खतरे में है तो अमेरिका को लगता है कि वहां पहुंचना चाहिए। उसे लगता है कि यदि कहीं वामपंथ पैर फैला रहा है तो उस पैर को वहां से हटाने की जिम्मेदारी उसकी है। वो भले ही पांच हजार से ज्यादा परमाणु बम लेकर बैठा है मगर कोई दूसरा देश यदि परमाणु बम बनाने की कोशिश करे तो उससे अमेरिका को खतरा महसूस होने लगता है और फिर धावा बोल देना अमेरिका का अधिकार हो जाता है!

मगर सवाल यह है कि क्या मूल रूप से यही कारण हैं या फिर कारण कुछ और है? विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे केवल खुद से मतलब है। दुनिया जाए भाड़ में! उसे मुनाफा होना चाहिए। उसकी ताकत ऐसी बनी रहनी चाहिए कि कोई उसे चुनौती नहीं दे पाए।

वह ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर राज करने की नीति पर चलता है और आज भी चल रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो दुनिया के 80 देशों में उसके 750 सैन्य अड्डे क्यों हैं? इतनी सारी जगहों पर सैन्य अड्डे बनाने के पीछे सीधा सा मतलब है कि उसे दुनिया पर राज करना है। यदि कोई देश उसकी बात न माने तो वह हथियार के बल पर बात मनवाने के लिए तैयार रहता है।

और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के हथियार उद्योग की है। भय का माहौल दुनिया के दूसरे देशों को हथियार खरीदने पर मजबूर करता है। ईरान के साथ जंग के बीच मध्य पूर्व के देशों को अमेरिका हथियार बेच रहा था। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। यदि जंग नहीं होगी तो हथियार बिकेंगे कैसे? 1953 से 1961 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रहे आइजनहावर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के नायक थे, ने हथियार उद्योग और सेना के बीच गठबंधन को लेकर कहा था कि यह एक अनिवार्यत युद्ध मशीन की तरह है जिसे लाभ कमाने के लिए हमेशा एक दुश्मन की आवश्यकता होती है। नए वक्त का भी सच यही है। जंग से अमेरिका का हथियार उद्योग खूब फल–फूल रहा है। ये हथियार कहां कितनी जांनें ले रहे हैं, इससे उसे क्या मतलब?

‘नारी शक्ति वंदन’: महिलाएं राजनीति में सुधार ला सकेंगी?

अभिलाष खांडेकर

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को फिर से गति देने का मोदी सरकार का निर्णय भले ही महिला राजनेताओं के वास्तविक कल्याण से अधिक एक राजनीतिक कदम प्रतीत हो, लेकिन लोकतांत्रिक समाज के सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कदम के समय को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संविधान संशोधन विधेयक पेश होने और संसद के दोनों सदनों में तार्किक और सार्थक बहस होने के बाद यह विवाद शायद शांत हो जाए। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा दशकों से चल रहा है। इसलिए, मैं इस सुधारवादी कदम का स्वागत करता हूं।

संविधान का 106वां संशोधन 2023 में पारित हुआ था और तब से यह उम्मीद की जा रही थी कि 2027 या 2029 तक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा लागू हो जाएगा। संविधान संशोधन का पारित होना ऐतिहासिक था, लेकिन पिछले तीन वर्षों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ नए मोड़ आ गए हैं, जिनमें परिसीमन प्रमुख हैं।

अब नए संशोधन (131) को खतरनाक बताया जा रहा है। इस महीने के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए, विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि भाजपा, जो पूर्वी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए विधेयक पर चर्चा शुरू की है और संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है।

बेशक, इस कानून में कई जटिल बाधाएं हैं, जिनमें निर्वाचन क्षेत्रों के भविष्य के परिसीमन और नए कानून निर्माताओं के रूप में मौजूदा सदस्यों के लिए प्रस्तावित 33 प्रतिशत कोटे के भीतर ओबीसी आरक्षण की मांग शामिल है। नए सांसदों की संख्या अब बढ़कर 850 तक होगी। निस्संदेह, आरक्षण से



लैंगिक समानता आएगी। महिला सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा को अक्षरशः और भावार्थ रूप से और आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन समाज के अन्य वर्गों के लिए और अधिक आरक्षण की मांग हमारे समाज के लिए घातक साबित होगी। सभी दलों के राजनेता लंबे समय से महिला नेताओं और भावी उम्मीदवारों को इस विधेयक का लालच देते आ रहे हैं।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यूपीए और एनडीए (कांग्रेस और भाजपा – जो दल नेता हैं) के गठबंधन इस निर्णायक कानून पर लगभग तीन दशकों से उलझे हुए थे। राजनीतिक इच्छाशक्ति का स्पष्ट अभाव रहा है। डॉ। मनमोहन सिंह ने जरूर इच्छाशक्ति दिखाई थी और उनकी सरकार ने मार्च 2010 में राज्यसभा में विधेयक पेश किया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं ले जा सकी। अब जबकि प्रधानमंत्री ने दृढ़ संकल्प दिखाया है, ऐसा प्रतीत होता है कि 1996 में देश के कानून निर्माण और शासन व्यवस्था में महिलाओं के साथ सत्ता साझा करने के गंभीर प्रयास के रूप में शुरू हुई यह उतार–चढ़ाव भरी यात्रा अपने गंतव्य के करीब पहुंच रही है। सब ठीक रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम विधानसभाओं के एक तिहाई हिस्से में विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाली जिम्मेदार महिलाओं को देखेंगे।

प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि संविधान संशोधन का मूल (या छिपा हुआ) मकसद क्या है? खैर, राजनीतिक दल अब तक इस मुद्दे पर हिचकियाते

ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने आरक्षण के अभाव में पुरुष प्रधान चुनावों में जीत हासिल की। सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी से लेकर नंदिनी सत्पथी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, सोनिया और प्रियंका गांधी, जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, उमा भारती, स्मृति ईरानी, सुप्रिया सुवे, आनंदीबेन पटेल या फिर ‘बैंडिट क्रीन’ फूलन देवी। हालांकि फूलन (मिर्जापुर से दो बार सांसद) को स्पष्ट कारणों से अन्य महिलाओं के बराबर नहीं माना जा सकता, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय मतदाताओं ने राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की महिला नेताओं पर भरोसा हमेशा दिखाया है। इस मामले में भारत ने अमेरिका समेत शक्तिशाली, आर्थिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है।

अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं

बनी है, लेकिन भारत में प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मु के रूप में दो राष्ट्राध्यक्ष और मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। इंदिरा गांधी ताकतवर प्रधानमंत्री थीं। महिला नेताओं को आमतौर पर संयमी, अपराध–विरोधी और भ्रष्टाचार–विरोधी माना जाता है।

लेकिन पंचायत के निचले स्तर के पदाधिकारियों

ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया; अनेक

स्थानों पर ‘पंच–पति’ ही सारे अधिकार नियंत्रित

करते थे और निर्णय लेने के साथ–साथ अकूत धन

कमाते थे। इस पृष्ठभूमि में और राजनीतिक व्यवस्था

में बढ़ते भ्रष्टाचार के दौर में, केवल आशा ही की जा

सकती है कि राजनैतिक समानता का यह अधिनियम

भारतीय राजनीति की व्यवस्था को त्रस्त करने वाली

विभिन्न बुराइयों पर अंकुश लगा पाएगा।

इस्लामाबाद के भव्य इवेंट का बिल कौन भरेगा?

विनोद पाठक

ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता खत्म हो चुकी है। दोनों देश अपने–अपने रास्ते लौट गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं कई सवाल, कई शंकाएं और एक अचूरी कोशिश का एहसास। सच कहें तो शुरूआत से ही यह उम्मीद कम ही थी कि इस वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकलेगा। फिर भी, दुनिया की नजरें इस पर टिकी थीं। शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद तनाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो हुआ, उसने उम्मीदों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की भूमिका को लेकर रही। उसने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन क्या वह सच में मध्यस्थ था? या सिर्फ एक ऐसा मंच, जहां दो पक्ष आकर अपनी–अपनी बातें कहकर लौट गए? कूटनीति में कई बार छोटी–छोटी बातें भी बड़ा संकेत दे जाती हैं। जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरा तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैन्य वर्दी में उनका स्वागत करते दिखे। उस पल में एक तरह का भाव था, जैसे कोई अपनापन या शायद एक खास संदेश, लेकिन जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो तत्कीर थोड़ी अलग थी। वही व्यक्ति, लेकिन इस बार सूट–बूट में, थोड़ा औपचारिक, थोड़ा झुका हुआ अंदाज।

यह अंतर शायद बहनों को सामान्य लगे, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल था या इसके पीछे कोई झुकाव भी था? जब कोई देश खुद को मध्यस्थ कहता है तो उससे उम्मीद होती है कि वह दोनों पक्षों के बीच बराबर की दूरी बनाए रखे। यहां वह संतुलन साफ नजर नहीं आया। इस पूरी वार्ता का एक और पहलू ध्यान खींचता है, जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया। पूरा इस्लामाबाद जैसे एक बड़े आयोजन में बदल गया था। सड़कों पर पोस्टर, शहर में सुरक्षा के नाम पर लॉकडाउन और ‘इस्लामाबाद टॉक्स’ का प्रचार, सबकुछ एक बड़े इवेंट जैसा लग रहा था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उनमें चर्चा इस बात की कम थी कि वार्ता में क्या हुआ और ज्यादा इस बात की कि मेहमानों को कैसी सुविधाएं मिलीं, फ्री वाई–फाई, अच्छा खाना, गीत–संगीत, शानदार इंतजाम। जैसी भारत के ले. जनरल (रिट.) केजेएस दिह्लो ने चुटकी ली,

‘होटल का बिल कौन भरेगा?’ यहां मन में एक सीधा सवाल उठता है, क्या कूटनीति अब समाधान से ज्यादा दर्शन बनती जा रही है? जब दो देश अपने–अपने अर्द्ध और दबाव के साथ बातचीत के लिए आते हैं, तब क्या यह माहौल उनके हालात के अनुरूप था? अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो समझ आता है कि इस वार्ता में शामिल दोनों पक्ष अपने–अपने बोझ के साथ आए थे। ईरान, जो हाल के संघर्ष में काफी नुकसान झेल चुका है। वहां के लोगों का दर्द, बुनियादी ढांचे की तबाही और भीतर की बेचैनी, यह सब उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ ही इस्लामाबाद पहुंचा होगा। दूसरी ओर, अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह सहज नहीं है। मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, उसकी रणनीति पर सवाल उठे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे वैसा समर्थन नहीं मिला, जैसा वह उम्मीद करता था। ऐसे में, जब दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठते हैं तो वहां केवल शब्द नहीं होते, वहां उनके देशों की स्थिति, उनकी मजबूरियां और उनकी प्रतिष्ठ भी साथ होती है। हालांकि, पूरे घटनाक्रम के बीच भारत का रुख दिलचस्प रहा। भारत ने इस वार्ता में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। न उसने मध्यस्थ बनने की कोशिश की, न ही खुद को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। देश के भीतर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, कहा गया कि भारत ने एक बड़ा अवसर गंवा दिया, लेकिन अब, जब वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है तो वही सवाल उल्टा खड़ा होता है, क्या हर मौके पर आगे बढ़ना जरूरी होता है? क्या हर संघर्ष में खुद को शामिल करना ही कूटनीति है? कई बार दूरी बनाकर रखना भी एक सोच–समझकर लिया गया फैसला होता है। शायद भारत ने यही किया। इस वार्ता में एक और बात साफ दिखी, दुनिया की बड़ी ताकतों की मध्यस्थ बनने को लेकर चुप्पी। न यूरोपीय संघ ने कोई ठोस पहल की, न चीन और न ही रूस ने खुलकर मध्यस्थता की। उल्टा, कुछ देश अपने–अपने पक्षों के साथ खड़े नजर आए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। नाटो भी इस पूरे मामले में उतना सक्रिय नहीं दिखा, जितनी उससे उम्मीद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति भी कई जगह सवालों के घेरे में है। ऐसे में सबसे बड़ा डर यही है, क्या यह अफसरफाला पात आने वाले बड़े टकराव की भूमिका बन रही है?



बॉडी नहीं बनाती ओमेगा-3, शाकाहारी लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं ये बीज

ओमेगा 3 एक जरूरी फैटी एसिड है, जिसे शरीर नहीं बना पाता है। इसलिए इसकी कमी का खतरा काफी ज्यादा होता है। जिससे बचने के लिए इन फूड्स का सेवन करना चाहिए।

शरीर को कई तरह के फैट की जरूरत होती है ताकि शरीर का काम सही चलता रहे। मगर ओमेगा-3 फैटी एसिड को बॉडी खुद नहीं बना पाती है और उसे फूड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। वरना शरीर में इसकी भारी कमी हो सकती है। सेल्स के फंक्शन के लिए यह न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होता है। शरीर में ओमेगा-3 की कमी से कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जिनके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने जानकारी दी है। एक्सपर्ट ने इसे पाने के लिए कुछ फूड्स खाने की सलाह भी दी है।

ओमेगा-3 की कमी से झेलनी होगी ये दिक्कतें ड्राई स्किन, हेयर और आई



हेल्दी स्किन और हेयर के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। वहीं, आंखों की नमी और रेटिना में इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी त्वचा, बाल और



गर्मी के मौसम में मसाज के फायदे

गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में बाहर निकलने पर बढ़ती धूप और गर्म हवा आपको परेशान कर देती है। इसके अलावा रोज की भागदौड़ भरी दिनचर्या लोगों को थका देती है। इसके बाद शरीर पर थकान हावी हो जाती है। इसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है। यदि आपको इस मौसम में तरोताजा रहना है तो मसाज एक अच्छा उपाय हो सकता है। मसाज लेने के बाद आप एक बार फिर से तन और मन से ताजगी महसूस करने लगते हैं।

मसाज के फायदे

- मसाज से मांसपेशियों की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का कार्य सही से होने लगता है।
- मसाज से ब्लड सर्कुलेशन सुचारु रूप से काम करता है।
- मसाज करने से नींद अच्छी आती है। जिसके चलते आंखों की रोशनी बढ़ती है। और स्किन चमकदार बन जाती है।
- मसाज करने के दौरान लंबी-लंबी सांस लेने से शरीर के अंदर मौजूद कई विकार बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शरीर में स्फूर्ति आ जाती है।
- मसाज रोज करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
- मसाज से रंग में निखार आता है और स्किन चमकदार बन जाती है।
- मसाज से मस्तिष्क में तरावट एवं मानसिक शक्ति का अनुभव होता है।
- मसाज के बाद स्किन के छिद्रों में तेल भरे रहने से जीवाणुओं शरीर के अंदर जाने का खतरा नहीं रहता है।

इनकी भी होती है मसाज

- माथे की मसाज
- गालों की मालिश
- दुड्डी की मसाज
- गर्दन की मसाज

आंखों में रूखापन कर सकती है। नाखून हो जाएंगे कमजोर नाखूनों की सेल्स को जोड़े रखने के लिए भी यह फैट जरूरी होता है। इसके कम होने पर सेल्स मेंब्रेन ढीले और कमजोर होने लगते हैं। जिससे नाखून कमजोर और नाजुक हो जाते हैं। बीमारियों का घर बनेगा दिल



ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से दिल बीमारियों का घर बन सकता है। क्योंकि, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जो कि नसों को सिकोड़ने और डैमेज करके दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण बनती हैं।

शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा-3 फूड शाकाहारी लोग इसे पाने के लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। इनमें इसका प्रकार अल्फा लिनोलेनिक एसिड (एएलए) प्रचुर मात्रा में होता है। साथ में फोर्टिफाइड दूध, योगर्ट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। ओमेगा-3 के नॉन वेजिटेरियन फूड मछलियों में ओमेगा-3 फैट काफी होता है। इसके लिए सैल्मन, मेक्रेल, टूना, सार्डिन आदि फैटी फिश का सेवन कर सकते हैं।



गर्मियों में तेज धूप, पसीना, गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी यानी शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। इस मौसम में शरीर से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने का खतरा होता है।

भारत में गर्मियों का मौसम जारी है और कई जगहों पर पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया है।

गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भाषण गर्मी में पंखा और कूलर भी साथ नहीं दे रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में गर्मी का सितम और बढ़ेगा और ऐसा वक्त आ जाएगा जब एसी भी काम नहीं करेगी। जाहिर है गर्मी का शरीर पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में तेज धूप, पसीना, गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी यानी शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। इस मौसम में शरीर से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने का खतरा होता है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आना, सिरदर्द, ऊर्जा की कमी, भ्रम और यहां तक कि बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। डाइट एक्सप्लेशन की फाउंडर और न्यूट्रिशनिस्ट पारुल के अनुसार, गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सिर्फ पानी काफी नहीं है। आपके खाने में कार्ब्स, विटामिन और मिनरल वाली चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। कुछ चीजें हैं जिनका गर्मियों में सेवन करने से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है और किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकता है।



कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आजकल की एक गंभीर और आम समस्या बन गई है। आजकल सिर्फ व्यस्क ही नहीं बल्कि युवाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब खानपान और सुस्त जीवनशैली इसका सबसे बड़ा कारण हैं। यह कोई आम समस्या नहीं है और इससे दिल से जुड़े रोगों, स्ट्रोक यानी दिमाग का दौरा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर के लिए जरूरी भी है लेकिन वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाद्य पदार्थों का पाचन, हार्मोन का उत्पादन और अन्य कई काम करता है। यह सभी कचरे और विषाक्त पदार्थों को वापस लीवर में पहुंचाता है। लेकिन एक खराब कोलेस्ट्रॉल भी है, जो धमनियों की दीवारों पर पट्टिका की एक परत बनाता है, जिससे रक्त का प्रवाह मुश्किल हो जाता है, जो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ खून की नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनमें गर्मियों में मिलने वाले कुछ फल भी शामिल हैं। चूंकि गर्मियों का मौसम जारी है, तो ऐसे में आपको इन सस्ते फलों का खून सेवन करना चाहिए जिससे शरीर से यह गंदा पदार्थ बाहर निकल सके और आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहे।

पपीता

फाइबर से भरपूर पपीता हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है और यह आंतों की भी सफाई करता है।

गर्मियों में खाएं ये चीजें चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर रहेगा ठंडा

केला और अवोकेडो

इन दोनों फलों में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा यह फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। यह दोनों इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखते हैं। इन दोनों का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है।

लौकी परिवार की सब्जियां गर्मियों के दिनों शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको लौकी परिवार की सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, करेला, तुरई आदि का खूब सेवन करना चाहिए। इनमें पानी की मात्रा होने के साथ सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

साबुजा सीड्स

इन छोटे-छोटे बीजों में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा यह ओमेगा-3 फैटी एसिड, पोटेशियम, विटामिन सी आदि का भी भंडार है। यह तत्व गर्मी को कम करते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं।

खट्टे फल

जूस वाले खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, कीनू

और मौसंबी आदि में जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखते हैं।

दही

घर की बनी दही पोषक तत्वों का खजाना है और यह पेट के लिए एक नैचुरल प्रोबायोटिक है, जो शरीर को ठंडा रख सकती है। आप खाने में दही या इसका रायता बनाकर इस्तेमाल करें।



आजकल सिर्फ व्यस्क ही नहीं बल्कि युवाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब खानपान और सुस्त जीवनशैली इसका सबसे बड़ा कारण हैं। कुछ खाद्य पदार्थ खून की नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनमें गर्मियों में मिलने वाले कुछ फल भी शामिल हैं।

खून की नसों में चिपके जिद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देंगे गर्मियों के ये 5 फल

अंगूर



एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंगूर फाइबर का एक बेहतर स्रोत है। इस तरह अंगूर का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को नैचुरली कम करने में मदद करता है। अंगूर वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिसे हृदय रोगों के पीछे एक और कारण बताया जाता है।

खट्टे फल

गर्मियों में सभी तरह के खट्टे फल खाना दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप अपने खाने में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं।

सेब



सेब एक ऐसा फल है, जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि शरीर में जमा अन्य गंदे पदार्थों को भी कम कर सकता है, सभी हृदय रोगियों को अपने खाने में सेब को शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को नैचुरली कम करने में मदद करता है। सेब में फाइबर पेक्टिन की मौजूदगी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है।

स्ट्रॉबेरी

एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए स्ट्रॉबेरी एक बेहतर परुट है। यह एंटीऑक्सिडेंट का बेहतर स्रोत है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह विटामिन का भंडार है और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है।



स्वाद के साथ सेहत की खान है आम

स्वाद के साथ फायदों की खान है आम। जी हां, आम को फलों का राजा माना जाता है। गर्मियां तो बिना आम के सेवन अधूरी है। आप कोई भी फल खा लें लेकिन आम को अपनी फ्रूट बास्केट में शामिल करना न भूलें। स्वाद के साथ आम खाने के कई फायदे हैं।

कैंसर से बचाव आम में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में फायदेमंद है। इसमें क्युसेटिन, एस्ट्रोगालिन और फिसेटिन जैसे ऐसे कई तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में मददगार होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल नियमित रखने में आम में फाइबर और विटामिन सी खूब होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल संतुलन बनाने में मदद मिलती है। पाचन क्रिया को ठीक रखने में आम में ऐसे कई एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। इससे भोजन जल्दी पच जाता है। साथ ही इसमें उपस्थित साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड शरीर के भीतर क्षारीय तत्वों को संतुलित बनाए रखता है।

स्मरण शक्ति में मददगार जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो उन्हें आम का सेवन करना चाहिए। इसमें पाया जाने वाला ग्लूटामिन एसिड नामक एक तत्व स्मरण शक्ति को बढ़ाने में उत्तेजक की तरह काम करता है। साथ ही इससे रक्त कोशिकाएं भी सक्रिय होती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आम खाने की सलाह दी जाती है। त्वचा के लिए है फायदेमंद आम के गुदे का पैक लगाने या फिर उसे चेहरे पर मलने से चेहरे पर निखार आता है और विटामिन सी संक्रमण से भी बचाव करता है।

मोटापा कम करने में मोटापा कम करने के लिए भी आम एक अच्छा उपाय है। आम की गुठली में मौजूद रेशे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। आम खाने के बाद भूख कम लगती है, जिससे ओवर ईटिंग का खतरा कम हो जाता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में

आम खाने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है।



बच्चों को सिखाएं हेल्दी फूड हैबिट

बच्चों के बड़े होने पर उन्हें पोषण देने के लिए जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें अच्छा पोषण दिया जाए। लेकिन उसके लिए सही शुरुआत करें और स्वस्थ खाना सिखाएं। बच्चे इन स्वस्थ आदतों को खुद अनुभव करके और दूसरों को देखकर सीखते हैं। बच्चों को अच्छी खाने की आदतें सिखाना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं होता है। इसके लिए आप नीचे दिए टिप्स भी अपना सकते हैं जिससे बच्चे सही समय पर स्वस्थ खाना सीखें जो उन्हें बड़े होने तक फायदा पहुंचाएगा। सभी साथ बैठकर खाएं एक परिवार के रूप में एक साथ खाना खाना जरूरी है। बच्चों को सिखाएं कि सभी साथ बैठें। इससे बच्चों के सामने आप हर तरह की सब्जियां खाकर दिखाएंगे तो वो भी आपसे सीखेंगे। साथ ही उन्हें लोगों के सामने व्यवहार करना भी आएगा। इससे एक फायदा होगा कि बच्चा खाना खाते समय फोन या टीवी भी नहीं देखेगा। बच्चों को चुनने दें जरूरी नहीं जो हम खा रहे हों वो

सभी चीजें बच्चे खाएं। बच्चों के लिए अलग से खाना न बनाएं लेकिन जो आप बना रहे हैं या बड़े खा रहे हैं वो सभी चीज बच्चों को जबरदस्ती न खिलाएं। बच्चों को खुद चुनने दें कि वो इन सबमें से क्या खाना चाहते हैं। अपनी कोशिश जारी रखें बच्चों को हेल्दी फूड हैबिट सिखाने में समय लग सकता है। ऐसे में अपनी कोशिश न छोड़ें। शुरुआत में बच्चे नखरे करेंगे लेकिन आपकी कोशिश जारी रही तो बच्चों की आदत भी बदलेगी। कभी-कभी बच्चों को यह चुनने दें कि खाने में क्या सब्जी बननी चाहिए। साथ ही उन्हें उसे बनाने में मदद के लिए कहें। लालच देकर न खिलाएं बच्चों को लालच देकर खाना खत्म करने को न कहें। बच्चों को डेजर्ट के लालच में खाना खाने को न कहें। कई माता-पिता इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बच्चे पूरा खाना खाएंगे तो उन्हें मिठाई मिलेगी। ऐसा न करें। उन्हें भूख के अनुसार खाना सिखाएं।

लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह

नई दिल्ली। मनोनीत राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद के लिए उन्हें सदन में मनोनीत किया था। हरिवंश का राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था और अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 7 के तहत शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की थी। राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह के निर्विरोध उपसभापति चुने जाने पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर कितना गहरा भरोसा है, पिछले कुछ समय में आपके अनुभव से सदन को कितना लाभ हुआ है, और आपने सभी

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को एक और झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दायर एक मामले में उनकी ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें इस मामले पर फैसला लेने के लिए असम की अदालत में जाने को कहा। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी उस अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद सामने आया है, जो उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी। यह आदेश दो जजों की बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंडुरकर शामिल थे। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि उसका 15 अप्रैल का आदेश उस अधिकार-क्षेत्र वाले कोर्ट की ओर बुरा असर नहीं डालेगा, जो कांग्रेस नेता की अर्जी पर फैसला करेगा। कोर्ट ने कहा कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही तेलंगाना हाई कोर्ट असम के उस कोर्ट के काम में दखल देगा, जो इस मामले की सुनवाई करेगा।

महिला आरक्षण बिल पर सपा नेता राम गोपाल का हमला

नईदिल्ली। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से पहले, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर इतिहास मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2023 में जब यह विधेयक पारित हुआ था, तब इसे सर्वसम्मति से समर्थन मिला था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद के बाहर पत्रकारों से विशेष बातचीत में कहा कि इतिहास रचा जा चुका है। यह कानून पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। ये लोग उस इतिहास को क्यों मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सबसे भ्रष्ट और बेईमान बताते हुए सांसद ने आगे कहा कि इस (वर्तमान केंद्र सरकार) से ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान कोई सरकार नहीं हो सकती। सपा सांसद का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदों से संशोधनों का समर्थन करने के आह्वान के एक दिन बाद आया है। मोदी ने कहा था कि वे कानून लागू करने का श्रेय नहीं लेना चाहते।

महिला आरक्षण: विरोध करने वालों को देश नहीं करेगा माफ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी की महिलाएँ खड़गपुर में एक रैली करेंगी, ताकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के लिए धन्यवाद दे सकें। इस अधिनियम के तहत महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार ने पत्रकारों से कहा कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हें धन्यवाद देने के लिए आज खड़गपुर में महिलाओं द्वारा एक रैली आयोजित की जाएगी। जो लोग इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें महिलाएँ और देश कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने परिसीमन बिल, 2026 का विरोध करने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्हें दक्षिण भारत के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसका विरोध करना महज राजनीति है। सौगत रॉय ने कहा कि विपक्षी पार्टियां संसद में परिसीमन के खिलाफ वोट करेंगी।

गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है कांग्रेस और सपा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधा और परिसीमन और महिला आरक्षण पर उनके रूख की तुलना गिरगिट से की। यह बयान परिसीमन और महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चल रही बहस के बीच आया है। उनकी यह टिप्पणी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 और 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन से इसके प्रस्तावित संबंध पर हो रही चर्चाओं के संदर्भ में है। एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने आरोप लगाया है। देश के एससी, एसटी व ओबीसी समाज के संवैधानिक/कानूनी अधिकारों आदि के मामले में, कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली यह पार्टी भी, महिला आरक्षण में, जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केन्द्र की सरकार के रहते हुये किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की है।

महाराष्ट्र सीएम का पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान, कहा-

यह चुनाव ममता बनाम जनता की लड़ाई है : देवेंद्र फडणवीस

कोलकाता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जनता के बीच की लड़ाई बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए फडणवीस ने कहा कि जनता ने सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए एक नई शुरुआत का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कहा, यह समर्थन दिखाता है कि बदलाव होने वाला है। यह भाजपा बनाम टीएमसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह चुनाव ममता बनाम बंगाल की जनता की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए एक नई शुरुआत का फ़ैसला किया है। टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल, जो कभी आर्थिक मामलों में शीर्ष पाँच राज्यों में गिना जाता था, अब खराब जीएसडीपी-से-कर्ज अनुपात के चलते कर्ज में डूब गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने कहा, आज अगर हम बंगाल के युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि यहाँ उद्योग-धंधे आएँ। पहले बंगाल देश के शीर्ष पाँच राज्यों में गिना जाता था। आज बंगाल पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। आज सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और कर्ज के अनुपात के मामले में बंगाल देश में पहले स्थान पर है। चुनावों से पहले भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए फडणवीस पश्चिम बंगाल में हैं।

राज्य में पहले चरण के चुनावों के लिए प्रचार के आखिरी दौर में, अखिल भारतीय तुणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया, जिसे वह बांग्ला विरोधी भाजपा करती हैं।

कूच बिहार ज़िले की अलग-अलग सीटों से



चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए, सीएम बनर्जी ने बंगाल की रक्षा करने, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने और इसकी धर्मनिरपेक्ष बनावट को बनाए रखने के लिए लड़ने का वादा किया।

जब तक मैं खड़ी हूँ, मैं इन बांग्ला-विरोधी जर्मीदारों को इस धरती के लोगों पर कोई भी दुष्ट या तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दूँगी। मैं बंगाल की रक्षा के लिए, उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जिनकी सेवा के लिए मुझे चुना गया है, इस खूबसूरत राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और हमारी धर्मनिरपेक्ष बनावट और समावेशी भावना को हर उस ताकत से बचाने के लिए लड़ूंगी जो इसे तोड़ने की कोशिश करती है।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और साथ में एक चुनावी रैली का वीडियो भी शेयर किया। लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है, जैसा कि आप हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, उनके पोस्ट में आगे कहा गया। अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि वह अपनी विचारधारा पर हमेशा कायम रही हैं और उन्होंने इस यात्रा का हर कदम लोगों के साथ मिलकर तय किया है। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, और विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएँगे।

स्टालिन हार के डर से परिसीमन विधेयक का कर रहे हैं विरोध: पलानीस्वामी

चेन्नई। परिसीमन विधेयक को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने शुक्रवार, 17 अप्रैल को कहा कि इस विधेयक से किसी भी राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव में हार के डर से इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कोयंबटूर में एक रोड शो में बोलते हुए कहा कि स्टालिन चुनाव में हार से डरे हुए हैं और मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने में असमर्थ हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि

परिसीमन तमिलनाडु के लिए बुरा है। पलानीस्वामी ने आगे कहा कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमिलनाडु आए थे, तब उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए स्टालिन की अपेक्षा से बेहतर तरीके से परिसीमन लागू करेगा। केंद्र सरकार का स्पष्ट मत है कि परिसीमन से किसी भी राज्य पर कोई असर



भाजपा की वनथी श्रीनिवासन के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके प्रमुख दोहरा खेल रहे हैं। उन्होंने कहा

नहीं पड़ेगा। वह अपने वादे पूरे करेगी। स्टालिन को छोड़कर सभी खुश होंगे। एडप्पाडी कोयंबटूर में एआईएडीएमके के आमन के, अरुणान, केपी. जयराम और भाजपा की वनथी श्रीनिवासन के लिए प्रचार कर रहे थे।

देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश : राहुल गांधी

नईदिल्ली। महिला आरक्षण और परिसीमन पर विशेष सत्र के दौरान बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं देश की राष्ट्रीय कल्पना में एक प्रेरक शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने जीवन में महिलाओं से प्रभावित हुआ है, जो समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। राहुल ने दावा किया कि इस विधेयक का महिला सशक्तीकरण से कोई इनामना नहीं है, 2023 में जो विधेयक इस सदन में पारित हुआ था वह महिला आरक्षण का विधेयक था।

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि सरकार ओबीसी भाइयों और बहनों को अधिकार देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक भारत की महिलाओं के पीछे छिपकर देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है। पूरा विपक्ष सरकार के इस प्रयास (महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों) को गिराने जा रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड़ा ने वह कर दिखाया जो वे 20 वर्षों में नहीं कर पाए। उनका इशारा वाड़ा के उस चाणक्य वाले व्यंग्य की ओर था, जिस पर गुरुवार को सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुरा दिए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा भारत की महिलाओं की आड़ में चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय... हर कोई जानता है कि भारत के समाज ने दलितों, ओबीसी और उनकी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया। गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना को दरकिनार करने और ओबीसी (अधिकांश वर्ग) की अनेकदेखी करने की कोशिश कर रही है, और उनके अधिकारों को छीन रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी गुजराज से हुई सनसनीखेज गिरफ्तारी

पटना। पुलिस ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने मुख्यमंत्री के आवास पर फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसकी पहचान बिहार के बांका जिले के निवासी 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांच के दौरान, उसका पता गुजरात के सानंद में चला। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, गुजरात और बिहार पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

गुजरात में मजदूर के रूप में काम करने वाले यादव को बाद में बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसे बिहार लाया जाएगा, जहां चल रही जांच के तहत उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकी अभियान ‘भारत की जनगणना 2027’ की मुख्यमंत्री



सचिवालय से डिजिटल माध्यम से शुरुआत की और राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जो आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 तकनीकी दृष्टि से एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें पहली बार पूर्णतः डिजिटल डेटा संग्रहण तथा स्व-गणना की सुविधा शुक्रवार से एक मई तक उपलब्ध रहेगी। चौधरी ने यह बात कही है। पिछले महीने अमेरिका ने रूस और ईरान से समुद्र के रास्ते तेल खरीदने पर 30 दिन की अस्थायी छूट दी थी। इसी छूट के तहत भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। यह खरीद करीब 200 मिलियन डॉलर की थी और पिछले सात साल में पहली बार भारत ने ईरान से तेल खरीदा है।

स्टेल प्रमुख समाचार

आईसीसी ने जारी किया महिला टी 20 चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल

नईदिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रवांडा में आयोजित होने वाली पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा। इसका आयोजन किगाली शहर में होगा, जहां गहंगा क्रिकेट स्टेडियम के दो सटे मैदानों पर मैच खेले जाएंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, पांच टीमों के इस टूर्नामेंट के पहले दिन इटली का मुकाबला मेजबान रवांडा से होगा, जबकि नेपाल का सामना अमेरिका से होगा। वानुअतु को पहले दिन बाई मिली है और 19 अप्रैल को वह रवांडा से भिड़ेगी। यह टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा शुरू किया गया एक नया आयोजन है, जिसका उद्देश्य सहयोगी सदस्य टीमों को अधिक अवसर प्रदान करना है। यह इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के साथ जुड़ता है, जिसका पहला संस्करण पिछले नवंबर में हुआ था, और यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अवसरों का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस प्रतियोगिता में आईसीसी के पांचों क्षेत्रों की शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों भाग ले रही हैं, जो इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। सभी पांचों प्रतिभागी टीमों ने 2025 के क्षेत्रीय महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में अपने प्रदर्शन के आधार पर टूर्नामेंट में जगह बनाई है। डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट 2 मई तक चलेगा और इसका उद्देश्य लगातार उच्च गुणवत्ता वाला मैच अनुभव प्रदान करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट को मजबूत करने और उभरती टीमों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के आईसीसी के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह आयोजन महिला टी20 वर्ल्ड कप के विस्तार के अनुरूप भी है, जिसमें 2026 तक 12 टीमों शामिल हो जाएंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 505 अंक उछला निफ्टी 24,353 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को हरे निशान पर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 0.65 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुए। एफएमसीजी और मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सपाट रुख के साथ 77,976.13 अंक पर खुला। दिन के दौरान इंडेक्स ने 78,553.45 के हाई और 77,726.23 का निचला स्तर छुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 504.86 अंक यानी 0.65 फीसदी की उछाल लेकर 78,493 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 24,165 अंक पर लगभग सपाट खुला। ट्रेडिंग सेशन के दौरान निफ्टी ने 24,371.90 का हाई और 24,096.05 के लो रेंज में कारोबार किया। अंत में यह इंडेक्स 156.80 अंक यानी 0.65 फीसदी की बढ़त लेकर 24,353 अंक पर बंद हुआ।

गौतम अडानी ने हासिल किया एशिया के नंबन 1 का ताज

नईदिल्ली। एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियेयर इंडेक्स के मुताबिक, अडानी की नेटवर्थ अब 92.6 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 8.10 अरब डॉलर की तेजी आई है। इसके साथ ही वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 16.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है। अंबानी एशिया में दूसरे और दुनिया में 20वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में 656 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क पहले नंबर पर बने हुए हैं।

एचडीएफसी लाइफ का चौथी तिमाही का मुनाफा 4% बढ़ा

नई दिल्ली। एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस की प्रीमियम आय बढ़ने के कारण मार्च, 2026 में समाप्त तिमाही में एकल शुद्ध मुनाफा चार प्रतिशत बढ़कर 495.65 करोड़ रुपए हो गया। इस जीवन बीमा कंपनी ने वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च अवधि में 476.54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। एचडीएफसी लाइफ ने नियामकीय सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम आय 25,829 करोड़ रुपए रही, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 23,765.56 करोड़ रुपए थी। इस बीच, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.10 रुपए का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की, जो उसकी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। कंपनी ने कहा कि अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 19 जून होगी।

भारत ने ईरान का तेल डॉलर नहीं युआन में खरीदा

नईदिल्ली। भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियां ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान अब चीनी मुद्रा युआन में कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, यह भुगतान मुंबई स्थित आईसीआईसीआई बैंक के जरिए किया जा रहा है, जो अपनी शंघाई शाखा के माध्यम से युआन में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले चार सूत्रों ने यह बात कही है। पिछले महीने अमेरिका ने रूस और ईरान से समुद्र के रास्ते तेल खरीदने पर 30 दिन की अस्थायी छूट दी थी। इसी छूट के तहत भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। यह खरीद करीब 200 मिलियन डॉलर की थी और पिछले सात साल में पहली बार भारत ने ईरान से तेल खरीदा है।

युद्ध के दौर में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

इस समय पश्चिमी एशिया में लगातार चल रहे संघर्ष तथा अमेरिका के द्वारा होमुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल दुलाई के महंगा होने और तेल आपूर्ति बाधाओं के कारण दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। हाल ही में 13 अप्रैल को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी में 3.21 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 3.11 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई।

भारत में खाड़ी देशों से आयातित कच्चे माल के महंगे होने और ईंधन, बिजली व गैस की कीमतों में वृद्धि से रसोई से लेकर कपड़े

और घरेलू उपकरण महंगे हुए हैं। खासतौर से आयातित केमिकल्स से जुड़े कच्चा माल के महंगे होने से पेंट सहित विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। साबुन, पेस्ट, बिस्किट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कई कंपनियां पेंकेट छोटे करने की रणनीति पर भी आगे बढ़ी हैं।

इतना ही नहीं, देश में महंगाई बढ़ने की एक नई चिंता यह भी है कि हाल ही में 13 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने वर्ष 2023 के बाद पहली बार बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूर्वानुमान पांच फीसदी अधिक या कम की मांडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है।



यद्यपि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मानसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, विवरण और फैलाव समान रहा तब खरीफ का उत्पादन कम नहीं हुआ, किंतु गैर-संचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम हो सकता है। साथ ही दलहन और तिलहन का कम उत्पादन

खाद्य मुद्रास्फीति पर असर डाल सकता है। ऐसे में महंगाई नियंत्रण के लिए राहत और सुधारों को तेजी से लागू करने की बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। हाल ही में वैश्वक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों व वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के लंबा खिंचने पर भारत की विकास दर में कमी और महंगाई के बढ़ने के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध और ऊर्जा कीमतों व आपूर्ति बाधाओं के कारण भारत में विकास दर धीमी हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।

मूडीज रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 6.8 प्रतिशत आंका गया था। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया, जो 2025-26 के 2.4 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में महंगाई दर के रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से ऊपर जाना चुनौतीपूर्ण होगा।

उम्मीद करें कि सरकार अमेरिका-ईरान टकराव के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए और अधिक रणनीतिक कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। कच्चे तेल के लिए रूस और वनेजुएला से आपूर्ति का रुख और बढ़ा जाएगा। सरकार के द्वारा खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी सहित उवरकों की उपयुक्त आपूर्ति के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने ‘मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया’ महाअभियान अंतर्गत 500 नए तरिया का किया शिलान्यास

जल संरक्षण से गांवों में बढ़ेगी समृद्धि: सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकां पहल मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान का आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत नवा तरिया, आय के जरिया के तहत प्रदेश में 500 नए तरिया (तालाब) के निर्माण का भी शिलान्यास किया। इससे जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस महाअभियान के तहत प्रदेशभर में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 15 अप्रैल 2026 तक 13,000 से अधिक डबरी निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि अभियान की गति और प्रभावशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि



जल ही जीवन और विकास का आधार है। ‘मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया’ अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन बना रहे हैं। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका डबरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, सब्जी उत्पादन और वृक्षारोपण जैसे विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे

लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण स्तर पर इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दीवार लेखन, बैनर, ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान तथा वयूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जशपुर विधायक मती रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित सुनिश्चित की गई है। हितग्राही परिवार की

महिला सदस्य का नाम नागरिक सूचना पटल में अंकित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की अधिकारिता और भागीदारी मजबूत हो सके। इसके तहत उन्नत तकनीक आधारित योजना निर्माण और ग्राम सभा की स्वीकृति के आधार पर कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से यह अभियान ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करेगा। मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान जशपुर सहित पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाते हुए ग्रामीणों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभर रहा है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सत्रिर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, विधायक पथलगांव मती गोमती साय, जशपुर विधायक मती रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।



परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत विवरण जैसे— नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय की जानकारी दर्ज की जा रही है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नागरिकों को एक डिजिटल संदर्भ संख्या प्राप्त हो रही है। यह संख्या भविष्य में सत्यापन के समय प्रगणकों को दिखानी होगी, जिससे डेटा मिलान का कार्य त्वरित और त्रुटिहीन होगा।

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों और 19,978 ग्रामों में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 62,500 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशाल टीम तैनात की है। इसमें 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्ववेक्षक शामिल हैं, जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। तकनीकी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 1855 भी सक्रिय है, जो नागरिकों के संश्यों का निराकरण कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान संकलित किया गया समस्त व्यक्तिगत डेटा जनगणना अधिनियम, 1948 के कड़े प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय है।

बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर वरिष्ठजनों का बढ़ाया हौसला



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित अत्याधुनिक डे-केयर केंद्र ‘सियान गुड़ी’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और आत्मीय संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वरिष्ठजन अत्यंत प्रसन्न नजर आए तथा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विकसित ‘सियान गुड़ी’ के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर बुजुर्गों को फूड बास्केट वितरित किए तथा धार्मिक पुस्तक,

शॉल एवं श्रीफल भेंटकर उनका सम्मान किया। उन्होंने समाज में वरिष्ठजनों के सम्मान और उनकी देखभाल के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में समाज तेजी से बदल रहा है। एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन और व्यस्त जीवनशैली के कारण अनेक बुजुर्ग दिन के समय अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अकेलापन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए ‘डे-केयर सेंटर डू सियान गुड़ी’ को परिकल्पना की गई है। यह भवन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, आत्मीयता और सक्रियता का एक सशक्त केंद्र बनेगा, जहां वे सुरक्षित वातावरण में दिन व्यतीत कर नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र का निरीक्षण करते हुए यहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की और इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श पहल बताया।

फॉरेस्ट ग्राउंड में बना बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित और अनुशासित कर रहा

रायपुर। महासमुंद जिले के ब्लॉक महासमुंद अंतर्गत फारेस्ट ग्राउंड में तैयार किया गया बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड विशेष सुविधा प्रदान करते हुए युवाओं और बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगस्त 2025 में पूर्ण होकर यह मैदान आम नागरिकों और खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। पहले शहर में बड़े खेल मैदानों की कमी और गलियों में बढ़ती वाहनों की भीड़ के कारण बच्चों और खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता था। निर्माण एजेंसी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित 4842 वर्ग फुट के सीमित क्षेत्र में विकसित यह बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड एक अभिनव समाधान के रूप में सामने आया। यह स्थान की कमी को दूर करने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित खेल वातावरण भी प्रदान करता है।बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड में दो पालियों में सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक और शाम 4:00 से 8:00 बजे तक संचालित इस ग्राउंड में स्कूली बच्चे, युवा और कामकाजी लोग अपनी सुविधा अनुसार खेल का आनंद ले रहे हैं। 15-20 मिनट के छोटे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस खेल ने व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों को भी फिटनेस और मनोरंजन का बेहतर विकल्प दिया है। रात में फ्लडलाइट की सुविधा के कारण खिलाड़ी कार्य के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। ग्राउंड में फ्लोर मेट और चारों ओर मजबूत नेटिंग की व्यवस्था होने से खेल सुरक्षित हो गया है तथा गेंद खोने या आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना भी समाप्त हो गई है। कम संख्या में खिलाड़ी भी आसानी से खेल सकेगा, जिससे यह हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त बन गया है। लगभग 25.07 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना ने जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूती दी है।

वनांचल को मिलेगा स्थायी उजाला, बिजली अधिकारियों को कार्य योजना बनाने निर्देश

रायपुर। प्रदेश क्षेत्र के वनांचल के गांवों में जहां अब तक सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की गई थी, अब शीघ्र ही मुख्य बिजली लाइन (ग्रिड) से जोड़ा जाएगा। इससे इन गांवों को अस्थायी सोलर व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और नियमित, स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इसका जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर के कोटा वनांचल क्षेत्र के चार गांवों का स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का आकलन किया तथा आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बिजली अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कोटा वनांचल में स्थित सरगोड़, छुइहया, चिचवा डबरी एवं परसापानी गांवों में पहले सोलर प्लांट के जरिए बिजली पहुंचाई गई थी। किंतु अब बिजली विभाग ने इन गांवों को मुख्य ग्रिड से



जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे ग्रामीणों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने गांवों में पहुंचकर सर्वे एवं तकनीकी निरीक्षण किया। इस दौरान एमडी श्री भीम सिंह कंवर ने कहा कि सोलर व्यवस्था एक अस्थायी समाधान था, लेकिन अब इन गांवों को मुख्य बिजली लाइन से जोड़कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।ग्रामीणों ने भी इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें सीमित सोलर बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे पंखा, टीवी, मोटर जैसे उपकरणों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

निजी स्कूलों की मांगे जायज सरकार अहंकार में डूबी: शुक्ला

रायपुर। निजी स्कूलों आरटीआई में भर्ती को लेकर चल रहा गतिरोध चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार हठ धर्मिता छोड़े तथा निजी स्कूलों से बातचीत कर मामले का समाधान निकाले। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तुरंत प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों से बात करे, गतिरोध समाप्त करें, ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने आर.टी.ई. लेकर आई थी, भाजपा सरकार उसमें अवरोध पैदा कर रही।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले आरटीई के भर्ती नियम में बदलाव कर निजी स्कूलों में नर्सरी को नही बल्कि पहली कक्षा को प्रवेश कक्षा माना गया जो सरासर गलत है। जबकि स्कूल की प्रथम कक्षा अगर नर्सरी है तो भर्ती उसी कक्षा से शुरू होगी। क्योंकि निजी स्कूलों में जो बच्चे खुद के खर्च से नर्सरी में भर्ती होते है वो प्रगति करते हुए पीपी वन/टू के बाद क्लास वन में पहुँचते है। जब क्लास वन की सीट पूर्व से शिक्षा ले रहे पीपी टू के बच्चा से भर जायेगी ऐसे में आरटीई के तहत गरीबो बच्चों के लिए सीट कहा बचेगा।

पीएटी से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विवि दुर्ग में प्रवेश का अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी एवं वानिकी विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026-27 के माध्यम से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग में बी.एससी. (ऑनर्स) उद्यानिकी एवं बी.एससी. (ऑनर्स) वानिकी के चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को व्यापम द्वारा निर्धारित नियमों एवं विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।बीएससी. (ऑनर्स) उद्यानिकी के लिए विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित 16 शासकीय महाविद्यालयों एवं 3 निजी महाविद्यालयों में कुल 1240 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं बी.एससी. (ऑनर्स) वानिकी पाठ्यक्रम के लिए 1 महाविद्यालय में कुल 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। इस संबंध में व्यापम द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

उद्योग मंत्री देवांगन ने महिला थाना का किया लोकार्पण



रायपुर। उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शुक्रवार को कोरबा स्थित सिविल लाइन थाना परिसर में कोरबा जिले के प्रथम महिला थाना का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह थाना जिले का पहला महिला थाना होगा, जो न केवल महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम में सहायक होगा, बल्कि उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करेगा। मंत्री श्री देवांगन ने थाना का शुभारंभ करने के बाद निरीक्षक भावना खांडेकर को थाना प्रभारी का विधिवत पदभार ग्रहण कराया। इस थाने में थाना प्रभारी सहित बलों की पदस्थापना की गई है। यह महिला थाना महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने विभिन्न परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले इस परिवार के बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही गर्मी में लगने वाले आमतीर पर आग से बचाव के उपाय हेतु पाम्पलेट का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 हेतु आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 के अंतर्गत प्रदेशभर के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, पारंपरिक पाक कला एवं सौंदर्यकला से जुड़े कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की पहल की गई है, ताकि वे अपनी कला को निरंतर आगे बढ़ा सकें और सांस्कृतिक परंपराएं जीवंत बनी रहें। संस्कृति विभाग द्वारा लोक कलाकारों को संबल देने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 हेतु आवेदन आमंत्रितयोजना के तहत चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही, चयनित कलाकारों को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और आगामी दो वर्षों तक वे पुनः इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश जारी



रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सकी जिले के डभरा तहसील अंतर्गत सिंधीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2026 को प्लांट की बॉयलर यूनिट-1 में स्टीम पाइप से जुड़े वाटर स्पलाई पाइप के ज्वाइंट में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु एवं बहुत से श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आयुक्त, बिलासपुर संभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के लिए निर्धारित बिंदुओं में घटना कब और कैसे घटित हुई, घटना के कारण एवं परिस्थितियाँ तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय शामिल हैं।जारी आदेश के अनुसार जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिवस के भीतर जांच पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करें।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

लोक कलाकारों को मिल रही नई पहचान, परंपराओं के संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा

चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित चिन्हारी योजना राज्य की समृद्ध लोक-संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाकारों को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण हो रहा है, बल्कि कलाकारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है।



तैयार हो रहा है, जो भविष्य में कला के संरक्षण और संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा।योजना के अंतर्गत चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें राज्य, राष्ट्रीय एवं

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही मेलों, उत्सवों और शासकीय कार्यक्रमों में इन कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे उन्हें

छत्तीसगढ़ चेंबर ने ट्रांसपोर्ट चेम्बर का किया विस्तार, नई कार्यकारिणी सूची जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि चेम्बर के कार्य में सहयोग करने एवं गतिशील बनाने के लिये चेम्बर में पदाधिकारियों का विस्तार करते हुए ट्रांसपोर्ट चेम्बर का गठन कर श्री हरचरण सिंह साहनी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तत्पश्चात ट्रांसपोर्ट चेम्बर का विस्तार करते हुए महामंत्री, कोषाध्यक्ष,कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख सलाहकार, उपाध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य पदों पर मनोनयन किया गया है। महामंत्री-सुखदेव सिंह सिद्ध, कोषाध्यक्ष- दिवाकर अवस्थी, कार्यकारी अध्यक्ष-गुरजीत सिंह संधू, रणजीत सिंह वालिया

सिंह संधू (रिम्पल), नीरज बंसल, सैयद आसिफ अली, पवन अग्रवाल, बलवीर सिंह, रोशन शर्मा, याकूब मोकाती एवं मुरारी अग्रवाल। कार्यकारिणी सदस्य-रूपक चंद्रवंशी, पिन्टू सिंह, उत्तम जायसवाल, रणजीत सिंह गिल, गुरविंदर सिंह, संधावालिया, रोहित कुशत्री, जगमिंदर सिंह बल, मनप्रीत सिंह संधावालिया, उमेश वर्मा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने उपरोक्त मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए यह उम्मीद की है कि सभी पदाधिकारी प्रदेश के व्यापार एवं उद्योग के हित में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ चेम्बर को एक नयी ऊँचाईयों पर लेकर जायेंगे।